

श्वेता विजन

“नजरिया साफ, ख़्ख़रें निष्पक्ष”

हिंदी दैनिक समाचार पत्र

देवरिया में
ओपी राजभर
बोले— पूर्वांचल
राज्य बना तो
मेरे समाज का
होगा पहला
मुख्यमंत्री,
सपा पर साधा
निशाना 2

सोमवार 21 सितम्बर 2026 हैदराबाद से प्रकाशित WEB SITE : Shwetha.co.in संपादक : रघुराम राजू कालीदिंडी पृष्ठ - 1 | अंक - 6 | वर्ष - 8 | मूल्य - 3₹

अयोग्य ठहराने का मामला : डर। दानम नागेंद्र ने तेलंगाना भू के आदेश के खिलाफ का रुख किया

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा दलबदल के लिए विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने को दानम नागेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही भाजपा विधायक दल के नेता एलेटी महेस्वर रेड्डी को प्रतिवादी बनाते हुए एक याचिका दायर की है। नागेंद्र की तरफ से अधिवक्ता सोमवार को सीजेआई (एचए) की पीठ के सामने याचिका का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें जल्दी सुनवाई की मांग की जाएगी। उनका मुख्य तर्क यह है कि कोर्ट किसी विधायक की अयोग्यता के बारे में विधानसभा अध्यक्ष के फैसलों का रिज्यू नहीं कर सकता और अध्यक्ष का फैसला सिर्फ सदन में सदस्य के व्यवहार पर आधारित होना चाहिए, उन्होंने तर्क दिया कि सदन के बाहर किसी सदस्य का व्यवहार, जैसे किसी दूसरी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और कहा कि चूंकि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष का फैसला सही था, इसलिए हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत दखल नहीं देना चाहिए था। यह कहा गया कि सदन के बाहर किसी सदस्य का व्यवहार सदन के अंदर की कार्यवाही से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं होता है।



इसलिए, अध्यक्ष ने अनुच्छेद 191(1)(2) के तहत निर्णय लेते समय दोनों मामलों को अलग-अलग माना। नागेंद्र ने साफ किया कि उन्होंने न तो अपनी बीआरएस की सदस्यता छोड़ी है और न ही कांग्रेस की सदस्यता ली है, और कहा कि सिर्फ तिरंगा स्कार्फ पहनने का मतलब कांग्रेस पार्टी में शामिल होना नहीं है। रेड्डी और बीआरएस विधायक पांडी कोशिक रेड्डी ने कैबिनेट फाइल की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि

उनकी दलीलें सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें सविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के साथ अनुच्छेद 191(2) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था। यह उनके खैरताबाद से बीआरएस विधायक के रूप में कार्य करते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में सिकंदराबाद से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के फैसले के आधार पर किया गया था।

वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता का निधन, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने जताया शोक

पीएम मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "पायल मेहता एक मेहनती पत्रकार थीं जो जमीन से मजबूती से जुड़ी रहीं और राष्ट्रीय मुद्दों की गहरी समझ उनकी पत्रकारिता में दिखाई देती थीं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि मेहता को काम के अलावा उनके उस स्नेहपूर्ण और आत्मीय व्यवहार के लिए भी याद किया जाएगा जिससे उन्होंने कई लोगों के जीवन को छुआ, उन्होंने कहा, "उनका अयान और असमय निधन अत्यंत दुःख है उनके परिवार, मित्रों और सहकर्मीयों के प्रति मेरी संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में शक्ति दे, ओम शांति।"



पायल (46) मुंबई की यात्रा पर थीं तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उनका निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "वह (मेहता) मुंबई की यात्रा पर थीं, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई, रात करीब दो बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, इलाज शुरू होने से पहले ही उनकी निधन थम गई।" क जर्नलिस्ट / चर्चसंलग्न, 100 पे दव उवतम, ज्द अपेपज जव डनउडपैन कमअमसचवकम, नवमैपदमे, तवनवक 2 'जोम' जोमव जव जीम

विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध एक कुशल पत्रकार बताते हुए कहा कि ऐसी प्रतिभाशाली और समर्पित पत्रकार का असमय निधन पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है उन्होंने 'एक्स' पर कहा, "मैं उनके शोकाकुल परिवार और मित्रों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हें इस गहरे दुःख को सहने की शक्ति दें, ओम शांति।" रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मेहता के निधन पर गहरा दुःख जताया, रक्षा मंत्री ने कहा, "वह हमें बहुत जल्द छोड़कर चली गईं, पायल बेहद

गर्भवती यूट्यूबर बहन की हत्या का खूनी बदला! जमानत पर बाहर आए जीजा को चाकू से गोदकर मार डाला

निजामाबाद (तेलंगाना): अपनी यूट्यूबर बहन की हत्या का बदला लेने के लिए जीजा का शराराह कल्ल और फिर सोशल मीडिया पर लाइव आकर जुर्म का कबूलनामा! निजामाबाद में प्रतिशोध और सनसनी से भरी एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस महकमे को भी हैरान कर दिया, कानून को चुनौती देने वाले और सोशल मीडिया पर लाइव कबूलनामा के इस सनसनीखेज मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यह घटना 17 सितंबर की है, आंध्र प्रदेश के हरिबा, वू निजामाबाद में अपनी मां से मिलने आए थे, 17 सितंबर को जब वह अपनी मां के साथ कार से जा रहे थे, तभी उनके शाले संतोष ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी, इस घटना के बाद संतोष ने एक वीडियो रिकॉर्ड



कर हत्या की बात कबूल भी की थी, सोशल मीडिया पर अपने जीजा यित्तारी हरिबाबू की हत्या करने का जुर्म कबूल करने के बाद, निजामाबाद पुलिस ने शनिवार को गांधी संतोष को गिरफ्तार कर लिया। इस खूनी वारदात के तार इसी साल मार्च महीने से जुड़े हुए हैं, कोरुपला के रहने वाले यित्तारी हरिबाबू ने मंडापुर गांव की 19 वर्षीय मशहूर यूट्यूबर वैष्णवी से शादी की थी, आरोप है कि शादी के बाद से ही

वैष्णवी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, 16 मार्च को चार महीने की गर्भवती वैष्णवी की बेरहमी से हत्या कर दी गई इस घण्ट्य हत्याकांड के बाद पुलिस ने वैष्णवी के पति हरिबाबू, उसकी मां लक्ष्मी और उसके दो भाइयों को दहेज उत्पीड़न व हत्या के आरोपों में गिरफ्तार कर करीमनगर जेल भेज दिया था। हत्या की थी आशंका जेल में बंद हरिबाबू और उसका परिवार कुछ दिन पहले ही अदालत से जमानत पर रिहा हुआ था, जमानत मिलने के बाद हरिबाबू की मां लक्ष्मी निजामाबाद में रहने लगीं, जबकि हरिबाबू खुद को सुरक्षित रखने के लिए आंध्र प्रदेश के अन्तपुर में रहने चला गया था, हाल ही में हरिबाबू अपनी मां से मिलने के लिए निजामाबाद आया हुआ था, वैष्णवी के

तेलंगाना: बड रेवंत रेड्डी ने वारंगल एयरपोर्ट के लिए नाम के सुझाव मांगे, डायरेक्टर ने दो नाम सुझाए

हैदराबाद: मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए जनता से अपील की, 'वारंगल एयरपोर्ट' का सपना मौजूदा कांग्रेस 'प्रजा पालना' (लोगों का शासन) में सच होने वाला है, कृपया नए एयरपोर्ट के लिए सही नाम सुझाएं, सरकार वारंगल में वर्ल्ड-क्लास एयरपोर्ट बनाने के सपने को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है, दस साल तक सत्ता में रहने के बावजूद बीआरएस सरकार वारंगल एयरपोर्ट बनाने में नाकाम रही, राज्य सरकार ने ममनूर एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीदने के लिए 298 करोड़ रुपये दिए हैं, जरूरी जमीन खरीदकर एयरपोर्ट्स ऑथॉरिटी को सौंप दी है, नया एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो पहले सिर्फ कागजों तक ही सीमित था, अब जमीन पर ठोस रूप ले रहा है, यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, यह वारंगल में इंडस्ट्री, टूरिज्म, शिक्षा, रोजगार और इन्फ्रेस्ट्रक्चर के लिए एक नया मोटव बननेगा, एक बार फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाने पर वारंगल और आस-पास के इलाकों के लिए आर्थिक विकास के नए मोके खुलेंगे, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जब कोई वारंगल से फ्लाइट ले सकेगा, ममनूर एयरपोर्ट तेलंगाना के लिए एक नए सिबल के तौर पर खड़ा होना चाहिए, रेवंत रेड्डी ने कहा, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और श्रीकांत ओडेला (दशहरा और



पैराडाइज के डायरेक्टर) ने एयरपोर्ट के लिए नाम के सुझाव के लिए मुख्यमंत्री की कॉल का जवाब दिया, संदीप ने अपने होमटाउन में एयरपोर्ट बनने पर खुशी जाहिर की और प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपने प्रस्तावित नामों की घोषणा की, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे होमटाउन वारंगल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, मैं एयरपोर्ट के लिए दो नाम सुझाना चाहूंगा, 'रुद्रमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एन-1)' और 'काकतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एन-2)', एयरपोर्ट का नाम किसी ऐसी चीज के नाम पर रखना सच में सही रहेगा जो वारंगल की रिय विरासत और कल्चरल स्पिरिट को दिखाए, इस एयरपोर्ट के सपने को हकीकत में बदलने की उनकी कोशिशों के लिए मैं गान्धीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारु को धन्यवाद देता हूँ, संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा, दशहरा और पैराडाइज फिल्मों के डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला ने भी ममनूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के अहम पड़ाव पर पहुंचने पर खुशी जाहिर की, उन्होंने कहा कि वारंगल सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की भावनाओं को समेटे हुए है, जो का केंद्र है, सीएम रेवंत रेड्डी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने 'सम्मक्का-सरक्का एयरपोर्ट' नाम का सुझाव दिया,

यूपी में पहले होते थे दंगे, हम कराते हैं मॉकड्रिल, सशक्त हुई पुलिसय सीएम योगी ने सपा को घेरा

सपा सरकार के कार्यकाल को याद कराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में हर दूसरे दिन दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू होता था, अलीगढ़, मेरठ में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में तो छह माह दंगे होते रहे, सामान्य नागरिक, व्यापारी की बात छोड़िए, प्रशासन में बैठे अधिकारी ही या पुलिस अधिकारी या जुडिशरी से लोग, उनके लिए माफिया एक चुनौती थे, माफिया का काफिला जा रहा हो तो जुडिशरी के अधिकारियों के वाहन को रोक दिया जाता था कि पहले माफिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने पूछा कि आज क्या कोई माफिया खुली जीप पर असलहा लहराते हुए कोई उपद्रव कर पायेगा? आज क्या उत्सव के पहले कोई उपद्रव करने का दुस्साहस करेगा? उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में क्या दंगों की श्रृंखला भूल न जाए कि दंगा कैसे होता था?



कराते हैं कभी-कभी, जिससे लोग भूल न जाए कि दंगा कैसे होता था? सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी पुलिस के बारे में पॉलिटिकल नजरिया अलग हो सकती है, उनको बोलना ही है जो कर नहीं पाए, वे हमेशा बोलेंगे, जिन्होंने अपनी अकर्मण्यता और अक्षमता का परिचय देकर उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था, उन लोगों को आज यूपी पुलिस पर या यूपी की व्यवस्था पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके निकम्मेपन और उनके निटल्लेपन को तो यूपी देख चुका है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी और भावी

रहा है? मैं कहता हूँ नहीं अब दंगा होता नहीं, हम मॉक ड्रिल दंगे का करवाते हैं कभी-कभी, जिससे लोग भूल न जाए कि दंगा कैसे होता था? सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी पुलिस के बारे में पॉलिटिकल नजरिया अलग हो सकती है, उनको बोलना ही है जो कर नहीं पाए, वे हमेशा बोलेंगे, जिन्होंने अपनी अकर्मण्यता और अक्षमता का परिचय देकर उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था, उन लोगों को आज यूपी पुलिस पर या यूपी की व्यवस्था पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके निकम्मेपन और उनके निटल्लेपन को तो यूपी देख चुका है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी और भावी

देवरिया में ओपी राजभर बोले— पूर्वांचल राज्य बना तो मेरे समाज का होगा पहला मुख्यमंत्री, सपा पर साधा निशाना

बैववेम म्ज् ठीतज

देवरिया : जनता इंटर कॉलेज, सोनूघाट के मैदान में रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) की सामाजिक समरसता रैली का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री एवं सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने सपा पर जमकर निशाना साधा और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास, शौचालय, बिजली, सड़क तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।



उन्होंने कहा कि विकास का लाभ जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जरूरत और पात्रता के

आधार पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। और सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। पूर्वांचल राज्य की मांग पर कहा कि यदि पूर्वांचल अलग राज्य बनता है तो सबसे पहला मुख्यमंत्री राजभर समाज का बेटा बनेगा। सपा मुखिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख लाल टोपी के साथ नीला गमछा लगाने का काम कर रहे हैं। सभी को याद है कि वह दलितों के कितने हिमायती हैं। अगर भाजपा के विधायक नहीं रहते तो पूर्व सीएम मायावती को इनके गुंडे मार दिए होते। भाजपा विधायकों ने उन्हें बचाने का काम किया था।

सुभासपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता राघवेंद्र राम द्विवेदी ने कहा कि अब डरने का समय नहीं है, बल्कि

इस महीने की 21 तारीख को पब्लिक इश्यूज रेजोल्यूशन फोरम

... डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. जी. लक्ष्मीशा विजयवाड़ा: 20 सितंबर, 2026.

डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. जी. लक्ष्मीशा ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट के लोगों की समस्याओं का तेजी से और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन देने के लिए खास कदम उठा रहा है। इसी के तहत, यह पता चला कि कलेक्टर के श्री विंगली वेंकैया कॉन्फेंस हॉल में 'पब्लिक इश्यूज रेजोल्यूशन फोरम' ऑर्गनाइज किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि पब्लिक इश्यूज रेजोल्यूशन फोरम सोमवार, 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक ऑर्गनाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और लोगों से सीधे पिटीशन लेंगे। उन्होंने कहा कि यह फोरम लोगों के लिए अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने और उन्हें सॉल्व करने के लिए जरूरी कदम उठाने में मददगार होगा। कलेक्टर ने सुझाव दिया कि अपनी समस्याओं से जुड़ी अर्जी देते समय लोग अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और समस्या से जुड़ी पूरी जानकारी साफ-साफ लिखें। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन के साथ समस्या से जुड़े सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट भी अटैच किए जाने चाहिए। जिन लोगों ने पहले भी इसी समस्या की शिकायत की है, वे अपनी पुरानी एप्लीकेशन रसीद/रिपोर्ट/रसीद साथ लाएं। उन्होंने कहा कि इससे वे पुरानी शिकायत की डिटेल्स देख पाएंगे और आगे की कार्रवाई जल्दी कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि सरकार ने 'डे सर्विस' शुरू की है ताकि लोग आसानी से अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकें। उन्होंने कहा कि शिकायत सुलझाने के प्रोसेस से जुड़ी जानकारी समय-समय पर मिलती रहे, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि जो लोग खुद कलेक्ट्रेट जाकर अपनी एप्लीकेशन नहीं दे सकते, वे भी सरकार की तरफ से दी जा रही 1100 टोल-फ्री कॉल सेंटर सर्विस का इस्तेमाल करके अपनी समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह, उन्होंने कहा कि उममावेंडु, च.हवअपद वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अपनी शिकायतें दर्ज करने का मौका है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि लोगों को उनके नजदीक सर्विस देने के लिए डिबीजन, मंडल ऑफिस और म्युनिसिपल ऑफिस में भी लोगों से एप्लीकेशन ली जा सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि लोग अपने इलाके के नजदीकी संबंधित ऑफिस में संपर्क करके अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. जी. लक्ष्मी ने लोगों से अपील की कि वे सरकार द्वारा दिए गए इस मौके का फायदा उठाकर जनता की समस्याओं को हल करें। उन्होंने कहा कि समस्याओं से जुड़ी पूरी जानकारी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अर्जी देने पर उनकी जल्दी जाँच की जा सकती है और नियमों के मुताबिक उन्हें हल किया जा सकता है। कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों को जनता से मिली हर अर्जी की जाँच करने और समस्या को हल करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य मकसद लोगों को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सर्विस देना है।



तेलुगु देशम पार्टी के नियमों का पालन करना चाहिए



जीवन व्यवहार में लाएंगे तो जाति का भेद नहीं रहेगा। यह हिंदू समाज के लिए कलंक है, इस कलंक से हमें मुक्ति चाहिए, यह काम किसी कानून या भगवान के अवतार या किसी के उपदेश से नहीं होगा, बकायदा दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए धारों तरफ बर्बा होती है, लेकिन सिर्फ इसको लेकर प्रस्ताव पास करने से पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी। हमें अपने घर, गली, कार्यक्रम में रिटायर्ड

पर्यावरण के बारे में जागरूक करना होगा, हमारी पिछली पीढ़ी ने सयंमिता जीवन जिया, इसलिए आज हम पहाड़, जंगल देख रहे हैं। क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को यह नहीं चाहिए? उन्होंने कहा कि परिवार से ही जीवन की अच्छी बातें शुरू होती हैं। परस्पर सहयोग, समाज के प्रति जिम्मेदारी, देश के विकास को लेकर घर के अंदर बर्बा करें, घर के बच्चे समाज के लिए कैसे जीवन बिता सकते हैं, इस पर विचार परिवार में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया आज अपनी अंतर्दुष्टि से बहुत परेशान है, राष्ट्रीय स्वामिमान को विकसित करके हम दुनिया के सामने मॉडल तैयार करें कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। नागरिकों के अपने कर्तव्य भी हैं। यह कर्तव्य सिर्फ कानून के डंडे या प्रशासन के नियम से नहीं चल सकते, हमें खुद सोच कर इस दिशा में चलना चाहिए, यदि हम खुद नहीं करेंगे तो डंडा तो है ही। नागरिकों के अपने

भोपाल में दत्तात्रेय होसबाले ने जातिवाद मिटाने की कड़ी बात, धर्मांतरण को लेकर किया जागरूक

भोपाल: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकारीबाह दत्तात्रेय होसबाले ने संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समाज में हो रहे धर्मांतरण जैसे कामों के लिए जागृत होने के लिए कहा है। उज्जैन में संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के बाद भोपाल में आरएसएस का बड़ा कार्यक्रम हुआ। इसमें संघ के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मध्य भारत प्रांत भोपाल विभाग के एकत्रीकरण कार्यक्रम को दत्तात्रेय होसबाले ने संबोधित किया। कार्यक्रम में रिटायर्ड लेफ्टिनेंस जनरल नरेन्द्र कोतवाल भी शामिल हुए। जातिवाद समाज के लिए कलंक, व्यवहार से दूर होगा। संघ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और आमजन शामिल हुए। कार्यक्रम में होसबाले ने कहा कि "समाज में जाति-धर्म के भेद को खत्म करने का काम करना चाहिए। जाति में बांटने से समाज कमजोर और खोखला बन जाता है। इसलिए लोगों को राष्ट्र के बारे में सोचना है। लोग यदि इसे अपने



लेफ्टिनेंस जनरल नरेन्द्र बरती और समाज में कर्तव्य और जिम्मेदारी को निभाना चाहिए।

तेलंगाना पुलिस अकादमी में बिहार पुलिस के 54 वैच के लिए सफल ट्रेनिंग प्रोग्राम

अमीर हुसैन, क्राइम ब्यूरो चीफ



जानकारी के आदान-प्रदान से कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सशक्त बनाना। छत्तीसगढ़ टटट तेलंगाना स्टेट पुलिस अकादमी में आज बिहार पुलिस के 54 वैच के लिए 6 दिन का इन-सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा हुआ। तेलंगाना

पुलिस अकादमी की डायरेक्टर की देखरेख में हुए इस प्रोग्राम में आधुनिक पुलिसिंग तकनीकों और टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की पर ध्यान दिया गया। इस मौके पर जल्लु की डायरेक्टर ने कहा कि अलग-अलग राज्यों के पुलिस अधिकारियों के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान पुलिसिंग के बेहतरीन तरीकों को साझा करने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के असरदार इस्तेमाल के साथ-साथ जनता से अच्छे संबंध, मानवीय दृष्टिकोण और प्रोफेशनल नैतिकता आधुनिक पुलिसिंग में बहुत जरूरी हैं। इस स्टडी टूर की मुख्य बातों में कई विभागों का दौरा शामिल था, जैसे: तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (जल्लु): एडवांस्ड साइबरक्राइम जांच और डिजिटल फोरेंसिक इंगल (जल्लु): इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशन और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण की रणनीतियां कमांड एंड कंट्रोल सेंटर: टेक्नोलॉजी-आधारित पब्लिक मॉनिटरिंग और खास ऑपरेशनल तरीके। छ भरोसा सेंटर और 'म टीएम': महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहतरीन तरीके। इस तरह के अंतर-राज्यीय सहयोग पूरे भारत में स्मार्ट, टेक्नोलॉजी-युक्त और नागरिकों के अनुकूल पुलिसिंग का रास्ता बनाते हैं।

अयोग्य ठहराने का मामला : डर। दानम नागेंद्र ने तेलंगाना भू के आदेश के खिलाफ का रुख किया

इडुक्की (केरल): लगातार कई घंटों की भीषण मूसलाधार बारिश के बाद, केरल के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में एक और त्रासदी हुई है। इडुक्की जिले में पहाड़ों के कोट्टकम्मूर में, बारिश के कारण भूस्खलन होने से दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। यह घटना तब हुई जब एक खेत में बने अस्थायी शौच पर पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया। जिससे भारी बारिश से बचने के लिए शौच में शरण लिए हुए वृक्षारोपण करने वाले श्रमिक मलबे के नीचे दब गए। कोट्टकम्मूर की निवासी चिन्नाम्मा और उनके भाई बालचंद्रन की मलबे में दबने से मौत पर ही मौत हो गई। जबकि मरिअम्मा गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों और आपातकालीन कर्मियों ने उन्हें बचाया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। चश्मदीदों के मुताबिक, पीड़ित अपने कपड़ों को सूखा रखने और बारिश रुकने का इंतजार करने के लिए पास के एक शौच में चले गए थे। हालांकि, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि शौच के ऊपर की पहाड़ी इस तरह अचानक ढह जाएगी। एक चश्मदीद ने बताया, "एक जोरदार आवाज के साथ, पत्थर और मिट्टी शौच पर गिरे। शौच पूरी तरह से तबाह हो गया, और कुछ ही पलों में, वे मलबे के नीचे दब गए।" प्रतिकूल मौसम के बीच साहसिक बचावतेज आवाज सुनने के बाद स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल की ओर भागे, लेकिन वहां उन्होंने एक शौच को भूस्खलन के मलबे में दबा हुआ पाया। उन्होंने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया। लगातार हो रही बारिश और दुर्गम इलाके के कारण, शुरुआत में वहां भारी मशीनरी ले जाना संभव नहीं था। फिर भी, स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए खुद ही मिट्टी हटाई। उनके तमाम प्रयासों के बाद भी, चिन्नाम्मा और बालचंद्रन ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। मरिअम्मा को बचावकर्मियों ने मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया और फिर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद, तलाश और बचाव अभियान को तेज करने के लिए पुलिस, राजस्व अधिकारी और दमकल विभाग घटनास्थल पर पहुंचे। प्रशासन अपनी खोज जारी रखे हुए है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपदा के समय आस-पास कोई और मौजूद नहीं था। उच्च पर्वतीय इलाकों में हाई अलर्ट और यात्रा पर रोकविभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा काफी बढ़ गया है। इसके साथ ही इडुक्की के वृक्षारोपण और जंगल से सटे इलाकों में भी बारिश तेज हो गई है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी जारी की है, जिसमें निवासियों से इन पहाड़ी क्षेत्रों में रात की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जिला कलेक्टर ने पहाड़ियों और नदी किनारों पर खतरनाक स्थानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों या राहत शिविरों में शिफ्ट होने का निर्देश दिया है। अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और उन्होंने लगातार भारी बारिश को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है।



‘ए’ निर्वाचन आयुक्त एसएस संधू और शीर्ष अधिकारियों को मिले नोटिस, इन दिग्गजों का भी लिस्ट में नाम

राजधानी दिल्ली में मतदाता सुचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (ए) अभियान ने प्रशासनिक गलतियों में हलचल पैदा कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत देश के निर्वाचन आयुक्त डॉ. एसएस संधू सहित कई सेवारत और सेवानिवृत्त शीर्ष नौकरशाहों, केंद्रीय सचिवों और दिग्गज हस्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। मतदान सुचियों में डेटा की विसंगतियों और पिछले रिकॉर्ड से मिलान न होने के कारण इन नामी हस्तियों को अपनी जानकारी सत्यापित कराने को कहा गया है। न्यू मोती बाग पोलिंग बूथ पर सामने आए सबसे ज्यादा नाम

दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यू मोती बाग मतदान केंद्र पर, जहां अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आवास स्थित हैं, कुल 593 मतदाताओं को नोटिस थमाए गए हैं। इसी सूची में निर्वाचन आयुक्त एसएस संधू का नाम भी शामिल है, जिन्हें नाम में मामूली अंतर के चलते नोटिस मिला है। इनके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिश्री, सेबी (एनए) अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे, प्रधानमंत्री के प्रधान वैधानिक सलाहकार अजय कुमार सुद, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव, मत्स्य पालन सचिव अभिलाष लिखी और व्यव सचिव बुमलुनमंग दुजलनाम जैसे कई प्रमुख सेवारत सचिव स्तर के अधिकारी भी इस सूची की चपेट में हैं। सीएजी के पद पर आसीन के. संजय मूर्ति को 'माता-पिता' के नाम में अंतर के कारण नोटिस जारी हुआ है।

दिग्गजों में पूर्व अध्यक्ष और जेएनयू के पूर्व वीसी एम. जगदेश कुमार, पूर्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, पूर्व पर्यावरण सचिव लीना नंदन और सीआईएसएफ की पूर्व महानिदेशक नीना सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर का नाम भी दस्तावेजों के मिलान न होने के कारण चर्चा में है। निर्वाचन आयोग की स्पष्ट



सफाई, घबरान की जरूरत नहीं देशभर में इस हाई-प्रोफाइल सूची के सामने आने के बाद और उठ रहे सवाल के बीच निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। आयोग का कहना है कि नोटिस मिलने मात्र से किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं माना जाएगा। यह केवल लॉजिकल डिसक्रिपेंसीज या पिछले ए डेटा से सीधे लिंक न हो पाने के कारण एक सत्यापन प्रक्रिया है। आयोग के नियमों के मुताबिक, जिन भी मतदाताओं या अधिकारियों को नोटिस मिले हैं, वे संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (म्पे) के समक्ष अपने जरूरी दस्तावेज और सही विवरण प्रस्तुत कर प्रविष्टियों का सत्यापन करा सकते हैं। दिल्ली में चल रहे इस व्यापक अभियान के तहत 33 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 29 अक्टूबर तक सभी आपत्तियों और नोटिसों का निस्तारण कर दिया जाएगा, प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजा

गया बुलावा

‘ए’ प्रक्रिया के दायरे में केवल सेवारत अधिकारी ही नहीं, बल्कि कई बड़े नाम, चीन एवं पूर्व प्रशासनिक चेहरे भी आए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, आप नेता मनीष सिंसोदिया, सांसद बांसुरी स्वराज, बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत आदि के नाम भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। उनके अलावा, पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष और जेएनयू के पूर्व वीसी एम. जगदेश कुमार, पूर्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, पूर्व पर्यावरण सचिव लीना नंदन और सीआईएसएफ की पूर्व महानिदेशक नीना सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर का नाम भी दस्तावेजों के मिलान न होने के कारण चर्चा में है। निर्वाचन आयोग की स्पष्ट

सफाई, घबरान की जरूरत नहीं देशभर में इस हाई-प्रोफाइल सूची के सामने आने के बाद और उठ रहे सवाल के बीच निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। आयोग का कहना है कि नोटिस मिलने मात्र से किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं माना जाएगा। यह केवल लॉजिकल डिसक्रिपेंसीज या पिछले ए डेटा से सीधे लिंक न हो पाने के कारण एक सत्यापन प्रक्रिया है। आयोग के नियमों के मुताबिक, जिन भी मतदाताओं या अधिकारियों को नोटिस मिले हैं, वे संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (म्पे) के समक्ष अपने जरूरी दस्तावेज और सही विवरण प्रस्तुत कर प्रविष्टियों का सत्यापन करा सकते हैं। दिल्ली में चल रहे इस व्यापक अभियान के तहत 33 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 29 अक्टूबर तक सभी आपत्तियों और नोटिसों का निस्तारण कर दिया जाएगा, जिसके बाद 4 नवंबर को अंतिम

पीएम मोदी की अनकही कहानियों का यूपी में होगा नाट्यमंचन, रंगमंच पर दिखेगी 25 साल की सेवा यात्रा



पूर्व अध्यक्ष और जेएनयू के पूर्व वीसी एम. जगदेश कुमार, पूर्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, पूर्व पर्यावरण सचिव लीना नंदन और सीआईएसएफ की पूर्व महानिदेशक नीना सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर का नाम भी दस्तावेजों के मिलान न होने के कारण चर्चा में है। निर्वाचन आयोग की स्पष्ट सफाई, घबरान की जरूरत नहीं देशभर में इस हाई-प्रोफाइल सूची के सामने आने के बाद और उठ रहे सवाल के बीच निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। आयोग का कहना है कि नोटिस मिलने मात्र से किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं माना जाएगा। यह केवल लॉजिकल डिसक्रिपेंसीज या पिछले ए डेटा से सीधे लिंक न हो पाने के कारण एक सत्यापन प्रक्रिया है। आयोग के नियमों के मुताबिक, जिन भी मतदाताओं या अधिकारियों को नोटिस मिले हैं, वे संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (म्पे) के समक्ष अपने जरूरी दस्तावेज और सही विवरण प्रस्तुत कर प्रविष्टियों का सत्यापन करा सकते हैं। दिल्ली में चल रहे इस व्यापक अभियान के तहत 33 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 29 अक्टूबर तक सभी आपत्तियों और नोटिसों का निस्तारण कर दिया जाएगा।

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का राहुल गांधी पर तंज, बोले- भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए जासूसी कर रहे

बहराइच : जिले के प्रमारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रविवार को बहराइच



दौरे पर थे। उन्होंने राहुल गांधी व पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एनएसए चीफ अजीत डोभाल की जमकर तारीफ की। राहुल गांधी द्वारा अजीत डोभाल पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है अपने अजीत डोभाल पर। राहुल गांधी ने जासूसी की है देश के खिलाफ और दूसरे देशों के पक्ष में उन्होंने कहा, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई जासूसी कर रहा है, तो उसका नाम है राहुल गांधी। देश के लिए जिसने जासूसी की है उसका नाम है अजीत डोभाल। दोनों की तुलना निरसंदेह एक सूरज और एक क्या कहें, कुछ कह नहीं सकता हूँ, इस स्तर की तुलना है। अजीत डोभाल भारत के लिए पाकिस्तान में नाई बन के रहे, चर्चा सुनते हैं कि कहीं दाढ़ी बना रहे थे, तो कहीं होटल में काम कर रहे थे। भारत के लिए किस-किस रूप में किया दिनेश प्रताप सिंह का राहुल गांधी पर तंज। (टपकमव बमकपजय 188)

प्राणों की बाजी लगा करके जो व्यक्ति भारत के लिए जासूसी करता हो, ऐसे जासूस पर मुझे गर्व है, हर भारतवासी को गर्व होगा। राहुल गांधी को सवाल उठाने के लिए भारत के संविधान ने और भारत की जनता ने अधिकृत किया है, तो लोकसभा में क्यों सवाल नहीं उठाते? जब लोकसभा में सवाल उठाने के लिए समय आता है, तो कंबोडिया में होते हैं, कहीं दूसरे देश में होते हैं, मौज-मस्ती करने के लिए चले जाते हैं भारत की जनता की सेवा के लिए और नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए राहुल गांधी के पास समय नहीं है। केवल यह आरोप मिथ्या लगाते हैं कि किसी की बात सुनी नहीं जाती। हमारे यहां 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। सबको अवसर है, चाहे जो बात कहे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के दक्षिणपंथी हिन्दू सांप्रदायिकता को कम्युनलिज्म से ज्यादा खतरनाक बताने पर उन्होंने कहा कि जिस भारत ने उनको उपराष्ट्रपति के रूप में सम्मान दिया, जिस भारत की रोटी और नमक खा करके वो भारत के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ, इतनी ऊंचाइयों पर अगर भारत न होता, तो किसी दूसरे राष्ट्र में उपराष्ट्रपति जैसे पद पर सम्मान पाने का हक शायद हामिद को कभी न मिलता। प्राणों की बाजी लगा करके जो व्यक्ति भारत के लिए जासूसी करता हो, ऐसे जासूस पर मुझे गर्व है, हर भारतवासी को गर्व होगा। राहुल गांधी को सवाल उठाने के लिए भारत के संविधान ने और भारत की जनता ने अधिकृत किया है, तो लोकसभा में क्यों सवाल नहीं उठाते? जब लोकसभा में सवाल उठाने के लिए समय आता है, तो कंबोडिया में होते हैं, कहीं दूसरे देश में होते हैं, मौज-मस्ती करने के लिए चले जाते हैं भारत की जनता की सेवा के लिए और नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए राहुल गांधी के पास समय नहीं है। केवल यह आरोप मिथ्या लगाते हैं कि किसी की बात सुनी नहीं जाती। हमारे यहां 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। सबको अवसर है, चाहे जो बात कहे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के दक्षिणपंथी हिन्दू सांप्रदायिकता को कम्युनलिज्म से ज्यादा खतरनाक बताने पर उन्होंने कहा कि जिस भारत ने उनको उपराष्ट्रपति के रूप में सम्मान दिया, जिस भारत की रोटी और नमक खा करके वो भारत के ऊपर इस

पंजाब: सीमा पार से तस्करी, फरीदकोट में चार गिरफ्तार, 47.

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने रविवार को सीमा पार से हेरोइन तस्करी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए फरीदकोट से चार लोगों को पकड़ा और उनके पास से 47.3 किलोग्राम हेरोइन, तीन पिस्तौल, तीन मेगजीन, 15 कारतूस और दो गाड़ियां जब्त कीं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (क्वच) गौरव यादव ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपियों के पंजाब में हेरोइन और गैर-कानूनी हथियारों की सीमा पार से तस्करी करने वाले नेटवर्क से संबंध है।

उन्होंने यह भी बताया कि फरीदकोट में थ्रू दर्ज की गई थी, आरोपियों के बड़े नेटवर्क के साथ संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अकुश, मंगल सिंह, सचिन उर्फ घसंजू और अनमोल सिंह के रूप में हुई है। सभी फिरोजपुर के रहने वाले हैं।

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (ए) गुरबंस सिंह बंस ने बताया कि आने वाले बाबा फरीद आगमन पर्व (हंड थपक [हउंद चतंड]) के लिए की गई विशेष नाकाबंदी के दौरान, सीआईए (अपराध जांच एजेंसी) फरीदकोट की एक टीम ने शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि एक हॉंडा सिटी कार को रोका। टीम ने तलाशी के दौरान चार लोगों को पकड़ लिया और 47.3 किलो. ग्राम हेरोइन की बड़ी खेप के साथ-साथ अवैध हथियार और गोला-बारूद भी जब्त कर लिया गया। उन्होंने आगे कहा, "जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह गिरोह राज्य में सप्लाय के लिए फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों में सीमा पार से ड्रोन के जरिये हेरोइन और हथियारों की खेप प्राप्त कर रहा था। आगे की जांच जारी है।" शनिवार को, काउंटर इंटारो की खेप प्राप्त कर रहा था। आगे की जांच जारी है।



ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (ए) गुरबंस सिंह बंस ने बताया कि आने वाले बाबा फरीद आगमन पर्व (हंड थपक [हउंद चतंड]) के लिए की गई विशेष नाकाबंदी के दौरान, सीआईए (अपराध जांच एजेंसी) फरीदकोट की एक टीम ने शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि एक हॉंडा सिटी कार को रोका। टीम ने तलाशी के दौरान चार लोगों को पकड़ लिया और 47.3 किलो. ग्राम हेरोइन की बड़ी खेप के साथ-साथ अवैध हथियार और गोला-बारूद भी जब्त कर लिया गया। उन्होंने आगे कहा, "जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह गिरोह राज्य में सप्लाय के लिए फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों में सीमा पार से ड्रोन के जरिये हेरोइन और हथियारों की खेप प्राप्त कर रहा था। आगे की जांच जारी है।" शनिवार को, काउंटर इंटारो की खेप प्राप्त कर रहा था। आगे की जांच जारी है।

शनिवार को, काउंटर इंटेलिजेंस (बी) अमृतसर ने सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक और मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 17 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की पहचान प्रिंस, मलकीत सिंह और राजिंदर सिंह के तौर पर की है, सभी अमृतसर के रहने वाले हैं। हेरोइन के अलावा, पुलिस टीमों ने एक कार भी जब्त की जिसका इस्तेमाल तस्करी के सामान को ले जाने में किया गया था। चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने रविवार को सीमा पार से हेरोइन तस्करी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए फरीदकोट से चार लोगों को पकड़ा और उनके पास से 47.3 किलोग्राम हेरो.

इन, तीन पिस्तौल, तीन मेगजीन, 15 कारतूस और दो गाड़ियां जब्त कीं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (क्वच) गौरव यादव ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपियों के पंजाब में हेरोइन और गैर-कानूनी हथियारों की सीमा पार से तस्करी करने वाले नेटवर्क से संबंध है। उन्होंने यह भी बताया कि फरीदकोट में थ्रू दर्ज की गई थी, आरोपियों के बड़े नेटवर्क के साथ संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अकुश, मंगल सिंह, सचिन उर्फ घसंजू और अनमोल सिंह के रूप में हुई है। सभी फिरोजपुर के रहने वाले हैं।

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (ए) गुरबंस सिंह बंस ने बताया कि आने वाले बाबा फरीद आगमन पर्व (हंड थपक [हउंद चतंड]) के लिए की गई विशेष नाकाबंदी के दौरान, सीआईए (अपराध जांच एजेंसी) फरीदकोट की एक टीम ने शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि एक हॉंडा सिटी कार को रोका। टीम ने तलाशी के दौरान चार लोगों को पकड़ लिया और 47.3 किलो. ग्राम हेरोइन की बड़ी खेप के साथ-साथ अवैध हथियार और गोला-बारूद भी जब्त कर लिया गया। उन्होंने आगे कहा, "जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह गिरोह राज्य में सप्लाय के लिए फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों में सीमा पार से ड्रोन के जरिये हेरोइन और हथियारों की खेप प्राप्त कर रहा था। आगे की जांच जारी है।" शनिवार को, काउंटर इंटेलिजेंस (बी) अमृतसर ने सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक और मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 17 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी।

पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की पहचान प्रिंस, मलकीत सिंह और राजिंदर सिंह के तौर पर की है, सभी अमृतसर के रहने वाले हैं। हेरोइन के अलावा, पुलिस टीमों ने एक कार भी जब्त की जिसका इस्तेमाल तस्करी के सामान को ले जाने

स्टाफ क्वार्टर निर्माण मामले में गरमाई सियासत: च.ब. की गोपनीय बातें सार्वजनिक होने पर अध्यक्ष अजय महावर ने जताई कड़ी आपत्ति



नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति (च.ब.) के अध्यक्ष और विधायक अजय महावर ने समिति की कार्यवाही को सार्वजनिक करने और इसे राजनीतिक रंग देने के प्रयासों पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोक लेखा समिति पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से नियमों के दायरे में रहकर काम कर रही है और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। इस पूरे मामले को विशेषाधिकार हनन के दृष्टिकोण से विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा। सोमवार को च.ब. अध्यक्ष अजय महावर ने बताया कि लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले स्टाफ क्वार्टर के निर्माण से जुड़ा मामला समिति के पास जांच के लिए आया है, यह जांच पूरी तरह से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (च.ब.) की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों और पैराग्राफ 2.5 के दायरे में की जा रही है। समिति मुख्य रूप से इस बात की तथ्यात्मक जांच कर रही है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वरों के निर्धारण के लिए पुरानी दर प्रणाली का उपयोग क्यों किया गया और लागत अनुमान का आधार क्या था, इसके अलावा, निर्माण क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी और उससे जुड़े वित्तीय प्रभावों की भी बारीकी से समीक्षा की जा रही है। निर्माण क्षेत्र और लागत में भारी वृद्धि पर सवाल च.ब. रिपोर्ट के अनुसार, स्टाफ क्वार्टर का निर्माण क्षेत्र लगभग 1,397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर करीब 1,905 वर्ग मीटर कर दिया गया था, इससे लगभग 18.88 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ा है। स्टाफ ब्लॉक के निर्माण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, च.ब. के मुताबिक, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्वीकृत धन का एक हिस्सा दूसरे मद में डायवर्ट किया गया। समिति यह जांच कर रही है कि यदि मूल योजना के अनुसार स्टाफ ब्लॉक नहीं बनाया गया, तो फंड के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी, इसके लिए स्क्षम प्राधिकारी कौन था और संबंधित भुगतान किस आधार पर किए गए, पुराने क्वार्टरों को गिराने, नए निर्माण, ठेकेदारों की पात्रता और भुगतानों से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। अजय महावर ने कहा कि लोक लेखा समिति की कार्यवाही पूरी तरह से गोपनीय होती है और अंतिम रिपोर्ट आने से पहले इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हाल ही में जब स्टाफ क्वार्टर के मामले में दस्तावेजों की छानबीन चल रही थी, तब कुछ गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक कर दिया गया और इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीतिक दल आपस में आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन च.ब. जैसी गरिमावन्वी संस्था को राजनीतिक विवाद में पसीटना उचित नहीं है। समिति की गोपनीय सामग्री को रोकने में विफलता पर प्रसारित करने और राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने के मामले को विशेषाधिकार के तहत विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष उठाया जाएगा। प्रस्तावित साइट विजिट स्थगित, जल्द होगी अगली कार्रवाई मामले को राजनीतिक रंग दिए जाने और स्वतंत्र जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों के चलते सोमवार को प्रस्तावित साइट निरीक्षण को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि समिति पर दबाव बनाने के हर प्रयास को विफल किया जाएगा। विधानसभा के नियमों और स्थापित संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए, सभी आवश्यक परिमिशान के साथ बहुत जल्द अगला साइट निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता लाना और च.ब. रिपोर्ट के सवालों के तथ्यात्मक उत्तर खोजना ही च.ब. का मुख्य कर्तव्य है।

5 रुपये से 40 रुपये तक पहुंचा कै-शुल्क, छात्र संघ के 79 साल के सफर में कई बार बदली व्यवस्था

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (कै-स) का नाम आते ही छात्र राजनीति, चुनाव और चार प्रमुख पदों की तस्वीर सामने आती है। इसू के इतिहास का एक पहलू उसका शुल्क भी है। कै-स के करीब 79 साल के सफर में सिर्फ चुनावी व्यवस्था ही नहीं बदली, बल्कि छात्रसंघ से जुड़ा शुल्क भी कई गुना बढ़ा है। विश्वविद्यालय प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक, 2012-13 तक छात्रों से कै-स के लिए महज 5 रुपये शुल्क लिया जाता था। विश्वविद्यालय प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक, इसू शुल्क में सबसे पहले बड़ा बदलाव वर्ष 2013-14 में हुआ, जब इसे 5 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये किया गया। 6 अगस्त 1947 को दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में छात्रों के प्रतिनिधि संगठन की स्थापना का प्रस्ताव सामने आया था। विश्वविद्यालय प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार, तत्कालीन कुल, पति ने परिषद को बताया था कि छात्रों का एक प्रतिनिधि समूह विश्वविद्यालय में छात्रों का संघ बनाना चाहता है, इसके लिए एक समिति गठित कर संविधान और कामकाज की प्रक्रिया तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया था। शुरूआती खर्च के लिए विश्वविद्यालय की ओर से 150 रुपये की सहायता देने की उम्मीद भी जताई गई थी। यही प्रस्ताव आगे चलकर इसू के संस्थागत सफर की शुरूआती कड़ी बना। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी, लेकिन छात्रों के लिए अलग प्रतिनिधि संस्था की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसी उद्देश्य से 9 अप्रैल 1949 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (कै-स) की स्थापना की गई, इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उस समय छात्रसंघ का मुख्य उद्देश्य छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करना, छात्रों की समस्याओं को उठाना और विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण को मजबूत करना था। शुरूआती वर्षों में छात्रसंघ का गठन प्रत्यक्ष चुनावों से नहीं होता था, प्रतिनिधियों के माध्यम से छात्र नेतृत्व का चयन किया जाता था। छात्रसंघ बनने के बाद उसके सामने आर्थिक आत्मनिर्भरता की समस्या खड़ी हो गई। 27 मार्च 1953 को विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति के सामने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से आर्थिक सहायता की मांग रखी गई, उस समय विश्वविद्यालय ने कहा था कि छात्र संघ को खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करने चाहिए। रिकॉर्ड के मुताबिक, उस वर्ष संघ को पहले ही 600 रुपये की सहायता दी जा चुकी थी, इसके एक



दिल्ली की आशा कार्यकर्ताओं के लिए सरकार ने खोला खजाना, मासिक प्रोत्साहन बढ़ाकर किया डबल

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की महिलाओं और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। राजधानी की प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, दिल्ली की रेखा सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मासिक प्रोत्साहन को दोगुना करने का निर्णय लिया है। अब आशा कार्यकर्ताओं का निर्धारित मासिक प्रोत्साहन 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से दिल्ली की 6,725 आशा कार्यकर्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की मुख्य रीढ़ है आशा पर्यार

बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आशा कार्यकर्ता दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी हैं, वे घर-घर जाकर नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां देती हैं, परिवारों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करती हैं तथा गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं की देखभाल में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों, विभिन्न जागरूकता अभियानों, स्वास्थ्य सर्वेक्षणों और सामुदायिक बैठकों के आयोजन में भी उनका योगदान सराहनीय रहा है। महामारी के कठिन दौर में भी इन कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना बेहतरीन सेवाएं दी थीं, सामान्यतः एक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों के स्वास्थ्य की देखरेख से सीधे जुड़ी होती है।

आर्थिक सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार लगातार इनके मानदेय और प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही थी, इस निर्णय से न केवल आशा कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सम्मान हुआ है, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे और अधिक उत्साह व समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगी। पेयजल किल्लत दूर होगी, किशाऊ परियोजना पर कैबिनेट ने जताया आभार



दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर हुए समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार और सहयोगी राज्यों के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते से राजधानी दिल्ली को 109.9 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) अतिरिक्त पानी किल्लत दूर होगी, बल्कि लंबे समय से चली आ रही पानी की मांग को दीर्घकालिक आधार पर मजबूती मिलेगी, उन्होंने कहा कि यह परियोजना राजधानी की जल सुरक्षा के लिहाज से एक मील का पत्थर साबित होगी। यमुना कपुनर्जीवन में मिलेगी मदद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किशाऊ परियोजना का लाभ केवल पेयजल तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे यमुना नदी के पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।

पर्याप्त जलप्रवाह मिलने से यमुना को स्वच्छ, निर्मल और पुनर्जीवित करने के दिल्ली सरकार के अभियानों को अमृतपूर्व गति मिलेगी। इसके साथ ही नृजल स्तर के पुनर्भरण (ग्राउंडवाटर रिचार्ज) में भी सहायता मिलेगी। छह राज्यों की सहमती से टला जल संकट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि गत जून माह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच इस पर सहमति बनी थी, जिसे अब औपचारिक समझौते का रूप दिया गया है। टीस नदी पर बनने वाली इस महात्वाकांक्षी परियोजना से ऊपरी यमुना बेसिन के राज्यों में जल बंटारण और प्रबंधन को बेहतर करने में मदद मिलेगी, सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल का आभार जताया है।

स्टायर्ड अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 2.12 करोड़ की साइबर ठगी, तीन आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार

जयपुर: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआइ) के रिटायर्ड अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) को डिजिटल अरेस्ट कर 2.12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में स्टेट सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जयपुर ने तीन आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर लाया गया। तीनों आरोपियों ने साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए रुपए के लालच में अपने बैंक खाते साइबर ठगों को किराए पर दिए, वारदात की शिकायत मिलने पर पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने बैंक खातों की पड़ताल की, तो आरो. पियों के बारे में जानकारी मिली। एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि इस मामले में रो. हित रेवण कटकधोंड, अम्बादास कालू जाधव और आमोल जगन्नाथ पवार की भूमिका सामने आने पर उन्हें महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर लाया गया है। अब साइबर ठगी की रकम की बरामदगी, रकम के आगे लेनदेन की कड़ियां जोड़ने और वारदात में शामिल अन्य साइबर ठगों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

पड़. ब्लडमत बापउम : बुजुर्ग दंपती को डिजिटल अरेस्ट कर 76 लाख की साइबर ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार, 50 लाख डोल्ड करवाए। वीडियो कॉल पर रखा, लाइव लोकेशन चालू करवाई: उन्होंने बताया कि परिवारी जीएसआई के एडीजी पद से रिटायर्ड हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 9 अगस्त से 18 अगस्त, 2026 के बीच साइबर ठगों ने मोबाइल कॉल और वाट्सएप कॉल के जरिए खुद को पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों के अधिकारी बनकर संपर्क किया। परिवारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होने, गिरफ्तारी वारंट जारी होने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाए का डर दिखाकर लगातार वीडियो कॉल पर रहने, लाइव लोकेशन ऑन रखने और

किसी अन्य से संपर्क नहीं करने को कहा गया। इस दौरान फर्जी नोटिस भेजकर साइबर ठगों ने अपने

बैंक खातों की जांच में रोहित रेवण कटकधोंड की भूमिका सामने आई। जबकि यस बैंक के खाते की



खातों में रकम भेजने का दबाव बनाया। दो खातों में जमा करवाई रकम: परिवारी ने दबाव में आकर 13 अगस्त को आईसीआईसीआई बैंक के एक खाते में 2.02 करोड़ रुपए और 18 अगस्त को यस बैंक के एक खाते 10.10 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर करवाए। जांच में सामने आया कि दो बैंक खातों में जमा साइबर ठगी की रकम को आगे अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर ठगी की रकम की लेयरिंग की गई, पुलिस ने बैंक खातों की केवाईसी, मोबाइल नंबर, सोडीआर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान की। आईसीआईसीआई

जांच से अंबादास कालू जाधव की भूमिका सामने आई। जांच में आमोल जगन्नाथ पवार की भूमिका भी सामने आई। पड़. कै. अधिकारी बन व्यक्ति को किया डिजिटल अरेस्ट, फर्जी खाते में करोड़ों की ठगी का डर दिखाकर रेंटे 10 लाख कृषि उत्पादों का व्यवसाय करता है रोहित: आरा. पी रोहित रेवण कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री का व्यवसाय करता है। उसकी 'ब्लूब्लैक च-जम्बूई चटप सज्ज' और 'टैन्जु ब्लू च्चम्बूई चटप' जम्बू च्चम्बू के नाम से फर्म है, पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास एक कॉल आया था, कॉल करने वाले शख्स

आनंद विहार कैफे फायरिंग मामले में मुख्य शूटर और उसकी प्रेमिका गिरफ्तार, तीसरे आरोपी की तलाश जारी

नई दिल्ली: शाहदरा जिले के आनंद विहार इलाके में कैफे के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल दो पिस्टल और स्कूटी बरामद की गई है। गोलीबा. री के दौरान स्कूटी चला रहे तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मौणा ने बताया कि 11 सितंबर की रात थाना आनंद विहार पुलिस को अस्पताल से दो युवकों के गोली लगने से घायल होने की सूचना मिली थी। घायलों की पहचान अशरफ और उसके दोस्त ईशान के रूप में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अजमेर से पकड़ा गया मुख्य शूटर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और टैक्निकल सर्विलांस की मदद



प्रेमिका ने की रेकी, फिर छिपने में भी की मदद जांच में पुलिस को अतू की प्रेमिका आफरीन की भूमिका का भी पता चला। आरोप है कि आफरीन

ने पीड़ितों की सटीक लोकेशन अतू तक पहुंचाई थी, वारदात के बाद उसने अतू को छिपने के लिए जगह उपलब्ध कराने में भी मदद की। इसके बाद पुलिस ने आफरीन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। तीसरे आरोपी की तलाश जारी पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल दो पिस्टल और स्कूटी बरामद कर ली है। गोलीबारी के दौरान स्कूटी चला रहे तीसरे आरोपी मुजम्मिल की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। डीसीपी के मुताबिक, इस कार्रवाई को आनंद विहार थाना एसएचओ इस्पेक्टर मनीष, इस्पेक्टर आशीष और एटीएफ इस्पेक्टर अर्जुन की टीम ने अंजाम दिया। पुलिस अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी के साथ-साथ वारदात में इस्तेमाल हथियारों और आरोपियों के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।

सोनभद्र में फर्जी दस्तावेजों से स्कैप लदा ट्रक कब्जाने का खुलासा, मिर्जापुर में स्कैप बेचने के बाद कटवाया ट्रक, तीन गिरफ्तार

सोनभद्र : रौबर्टसगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 24 टन से ज्यादा स्कैप से लदे ट्रक को अगवा कर, उसे कबाड़ में कटवाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में तीन शक्ति बंदमाराओं को गिरफ्तार किया है, जबकि दो मुख्य आरोपी फरार हैं। मेन रोड रेनुकूट, शिवा पार्क के रहने वाले ब्रह्मप्रसाद पाण्डेय ने रौबर्टसगंज थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि 9 सितंबर 2026 को बरगवा, सिंगरीली मध्य प्रदेश से 24 टन 900 किलो स्कैप आवरण खरीदकर ट्रक संख्या नंबर 29881 से महामाया इस्पात कंपनी, चुनार, मिर्जापुर के लिए भेजा था। 10 सितंबर को ट्रक चालक से फोन पर संपर्क किया गया तो उसने बताया कि लोड़ी टोल प्लाजा के पास सुबह करीब 5:30 बजे अज्ञात व्यक्ति ने खुद को वाहन स्वामी बताकर ट्रक से उतार दिया। 500 रुपये देकर वाराणसी भेज दिया और कहा ट्रक को ले जाएगा। उसके बाद से स्कैप लदा ट्रक लापता हो गया। पीड़ित की तहरीर पर थाना रौबर्टसगंज पर मुक. दमा अपराध संख्या 757/2026 केअंतर्गत धारा 316(2), 338, 336(2), 340(2) उछे के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक थाना रौबर्टसगंज धर्मेन्द्र कुमार सिंह एवं एसओजी प्रभारी राम स्वरूप वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। विवेचना के दौरान वाहन संख्या नंबर 29881 का मालिक मनोज यादव पुत्र प्रेमप्रकाश यादव मिला। तकनीकी जांच, ब्जट फुटेज और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को अहम सुरांग मिले। जांच में खुलासा हुआ कि नीरज यादव और



उमाकान्त यादव ने आपस में मिलकर साजिश रची। दोनों ने प्लान बनाकर स्कैप लदे ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और मिर्जापुर ले गए। वहां ट्रक में लदे स्कैप को बेचने के बाद ट्रक को कबाड़ गोदाम में ले जाकर कटवा दिया और उसके कल-पुर्जे अलग-अलग कर दिए। 19 सितंबर को थाना रौबर्टसगंज पुलिस और एसओजी टीम ने मिर्जापुर स्थित 39वीं वाहिनी गेट नं-02 के सामने स्थित कबाड़स्कैप गोदाम पर दबिश दी। मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान धीरज यादव (33) पुत्र पन्नालाल यादव, निवासी घमहापुर, थाना विंध्याचल, मिर्जापुर, भरत लाल उर्फ बल्ला साहू (50) पुत्र रवीश्वरी ब्रह्मदेव साहू, निवासी सोमरा बैसुखिया, कोतवाली वेहात, मिर्जापुर और आकाश गुप्ता (25) पुत्र कैलाश गुप्ता, निवासी रेवडा परसपुर, कोतवाली भदोही के रूप में हुई है। पूछताछ में भरत लाल उर्फ बल्ला ने बताया कि वह कबाड़ का कारोबार

करता है और 11 सितंबर को नीरज और उमाकान्त ट्रक लेकर उसके पास आए थे। धीरज यादव ने बताया कि नीरज यादव उसका छोटा भाई है और उमाकान्त उसका रिश्तेदार है। तीनों ने मिलकर ट्रक को हासिल करने की योजना बनाई थी। वहीं आकाश गुप्ता ने बताया कि यह स्कैप के लेन-देन का काम करता है और 14 सितंबर को उसने यह स्कैप खरीदा था, जिस बाद में गलाने के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने आरो. पियों के पास से और मौके से 5 लाख नकद समेत कुल 20 लाख रुपये की बरामदगी की है। मौके पर बरामद ट्रक के कटे हुए हिस्सों और चेसिस नंबर की पहचान वाहन स्वामी द्वारा कर ली गई है। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता नीरज यादव और उमाकान्त यादव सहित अन्य अभियुक्तों की गूमिका की जांच की जा रही है और अग्रिम विवेचना जारी है। फिलहाल गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।

लखनऊ में कारोबारी का अपहरण, 9 घंटे तक गाड़ी में लेकर घूमते रहे, पैसा मिलने पर शहीद पथ पर छोड़कर भागे

लखनऊ : कृष्णानगर में खुद को पुलिस अधिकारी बताकर कारोबारी का अपहरण करने वाले अंतरराज्यीय गिराह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने गिराह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरो. पियों के पास से दो तमंचे, तीन कारतूस, दाई लाख रुपये नकद, स्कॉपियों, दो फर्जी नंबर प्लेट और चार कूटरचित पुलिस अधिकारी के आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने एक कारोबारी को फर्जी पुलिस आईडी कार्ड दिखाकर पूछताछ के बहाने गाड़ी में बैठाया, फिर असलहे के बल पर डरा-धमकाकर उसकी पत्नी से फिरोती की मांग की थी। डीसीपी दक्षिणी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया, 12 सितंबर को सुदर्शन घोष अपने ऑफिस जा रहे थे। इसी दौरान आरो. पियों ने रास्ते में उन्हें रोक और खुद को पुलिस अधिकारी बताया। 9 घंटे तक कारोबारी को लेकर गाड़ी में घूमते रहे। (टपकमव बमकपजय म्जट टीतंज) आरोपियों ने फर्जी पुलिस आईडी कार्ड दिखाकर उन्हें भरोसे में लिया और पूछताछ के नाम पर जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद असलहे के बल पर उन्हें धमकाया और मारपीट की। आरोपियों ने सुदर्शन से उनकी पत्नी को फोन करवाकर फिरोती की रकम मंगाने को कहा। इस दौरान आरोपियों ने सुदर्शन की पत्नी से नकदी और जेवर की भी मांग की। आरोपी 9 घंटे तक गाड़ी में व्यापारी कइो गिराह पहले उनकी रेकी करता है, 1 लेकर घूमते रहे। सुदर्शन के ड्राइवर के जरिए 13 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर अहो गिराह पहले उनकी रेकी करता है, 1 रोपियों तक पहुंचाए गए। इसके बाद



बंदमारा सुदर्शन को शहीद पथ के पास छोड़ कर फरार हो गए। डीसीपी मोहम्मद मुश्ताक ने बताया, घटना के खुलासे के लिए आठ टीमों लगाई थीं। टीमों ने करीब 220 से 240 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले। इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्य, मैनुअल इनपुट और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों की पहचान अनुराग, लबी कुमार, दीपाशु कुमार, अनुराग कुमार, आकाश चौधरी और मनीष कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उनका गिराह कई राज्यों में सक्रिय है और गिराह ऐसे लोगों की तलाश करता था, जिनके पास काफी पैसा हो गिराह पहले उनकी रेकी करता है, फिर मौका देखकर वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस के मुताबिक, इस घटना में गिराह के एक सदस्य ने सुदर्शन के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद आरोपियों ने लखनऊ में रहकर उनकी गतिविधियों और आने जाने की रेकी की थी। गिराह वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर कूटरचित नंबर प्लेट डीसीपी दक्षिणी की ओर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया है।

जाति-धर्म के मुद्दे पर लोगों को बांट रही भाजपा, च्व। सपा का धोखाय ठैच प्रदेश अध्यक्ष ने बोला हमला



अयोध्या: यूपी के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। रविवार को बीकापुर विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे जितेंद्र सिंह बबलू द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत कई बड़े बसपा नेता मंच पर दिखाई दिए। इस सम्मेलन जातीय मुद्दा हावी रहा। जहां प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और समाज के बीच जाति-धर्म के मुद्दे पर बांटने का आरा. प भी लगाया। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल (टपकमव बमकपजय म्जट टीतंज) इस आयोजन को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बरसा करेगे। वहन जी की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में खुब काम किया गया। कहा कि कानून-व्यवस्था पर सबसे अच्छा काम वहन जी की सरकार हुआ। 6 लाख से ज्यादा नौकरी देने का काम किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने नौजवानों को निकाला था, उस पर रोक लगाने का काम वहन जी ने किया। आज भाजपा की सरकार में नौजवान बहुत परेशान हैं। प्रदेश की जनता वहन जी की सरकार को याद

कर रही है। निश्चित तौर पर 2027 में वहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम जनता करेगी। कंडेला हत्याकांड को लेकर कहा कि हमारे गांव के बगल में घटना हुई है, स विश्वनाथ पाल ने मीडिया से बात की, कहा कि सपा का पीडीए एक धोखा है। अगर वह पीडीए का विजनता वहन जी की सरकार को याद कास चाहते तो पिछड़े वर्ग, ओबीसी वर्ग की बैकलाग भर्ती नहीं रोकते। वहन जी ने जो प्रमोशन किया, उनका डिमोशन नहीं करते। पीडीए का विकास चाहते तो विधानसभा में संविधान की धजिया उड़ाते हुए उनके आरक्षण का बिल नहीं फाड़ते। पिछड़ा, दलित में बहुत से महापुरुष का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज के लिए काम किया। वहन जी ने जिला बनाया, विद्यालय का नाम रखा, मेडिकल कॉलेज का नाम रखा, इसको बदल कर उनका अपमान नहीं करते। पीडीए का मतलब परिवार दल एलाइंस है। भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा, कहा कि भाजपा बड़े-बड़े वादे करके समाज के बीच में गई थी। जबकि आज बच्चों की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। नौकरियों का पर्या लीक हो गया।

यहां तक कि भगवान श्री राम के घर योरी हो गई, तो भाजपा पर क्या भरोसा करेंगे। वहन जी की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में खुब काम किया गया। कहा कि कानून-व्यवस्था पर सबसे अच्छा काम वहन जी की सरकार हुआ। 6 लाख से ज्यादा नौकरी देने का काम किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने नौजवानों को निकाला था, उस पर रोक लगाने का काम वहन जी ने किया। आज भाजपा की सरकार में नौजवान बहुत परेशान हैं। प्रदेश की जनता वहन जी की सरकार को याद कर रही है। निश्चित तौर पर 2027 में वहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम जनता करेगी। कंडेला हत्याकांड को लेकर कहा कि हमारे गांव के बगल में घटना हुई है, जो बहुत दुखद है। मौर्या परिवार के साथ बहुत अत्याचार व अन्याय हुआ है, जिस पर सरकार पूरी तरह से फेल रही है। आरोपियों की भी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही थी। कुछ दिन पहले कुशमाहा ने एक लड़की की लाश मिली थी। बस्ती में हत्या, गोरखपुर में दो मासूमों मार दिया गया था। इलाहाबाद, हमीरपुर, बलिया में घटना हुई है। आज पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। यह सरकार हर मुद्दे पर फेल है।

राजस्थान निकाय चुनाव में माकपा से भी बुरी स्थिति में बसपा, फिर भी मायावती खुश, आखिर क्या हैं इसके मायने?

लखनऊ : देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहें मायावती की पार्टी बसपा का प्रदर्शन दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है। कई राज्यों में बसपा का सुपडा भी साफ है। उत्तर प्रदेश तक में बसपा का अस्तित्व नहीं बचा है। बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने के लिए जूझ रही है। बड़ी जीत तो दूर, छोटी-छोटी खुशियों में ही पार्टी की मुखिया गदगद हो जाती हैं। हालिया राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ 19 पार्षद जीतने पर मायावती इस कदर खुश हुई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर खुशी जता डाली, जबकि हालत ये है कि देशभर में लगभग खत्म होने के कारण पर खड़ी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी बसपा से दोग. ना पार्षद जितवाने में सफलता पाई है। देशभर में मायावती की पार्टी की इस हालत की वजह पार्टी के बड़े नेताओं का साथ छोड़ जाना तो है ही, अब अंदरूनी कलह भी बड़ा कारण बन रही है। बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने के लिए जूझ रही है। (टपकमव बमकपजय म्जट टीतंज) राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाना चुनौती : उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बीएसपी का ग्राफ गिरता ही जा रहा है। चुनाव चाहे कोई भी हो, पार्टी की सीटें तो कम होती ही जा रही हैं। मत प्रतिशत भी कम होता जा रहा है। कई बार तो राजनीतिक दलों ने यहां तक सवाल खड़े किए कि अब निर्वाचन आयोग को फिर से राष्ट्रीय पार्टियों का रिव्यू करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की अब यह स्थिति नहीं बची है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बच पाए। 19 काउंसलर की जीत में ही बसपा प्रसन्न : हाल ही में राजस्थान में हुए 309 नगर निकाय चुनाव में 10,244 वार्ड में वोट डाले गए थे। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 19 वार्ड में काउंसलर को जीत दर्ज करवाने में सफल हो सकी। भाजपा राजस्थान नगर निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी। भाजपा ने 4179 सीटों पर जीत दर्ज कर पाने में



सफलता हासिल की, कांग्रेस को 3613 सीटें मिलीं, 2273 सीटों पर निर्दलीय जीते। राजस्थान निकाय चुनाव में बसपा का हाल राजस्थान निकाय चुनाव में बसपा का हाल. (विजय बमकपजय म्जट टीतंज) कम्युनिस्ट पार्टी को मिले 38 सीट : आरएलपी ने भी 63 सीटों पर जीत हासिल की, देश में लगातार सिमटती दिख रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राजस्थान नगर निकाय चुनाव में 38 सीटों पर जीत दर्ज की, यह बहुजन समाज पार्टी को मिली सीटों से ठीक दोगुना है। इसके बावजूद मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. ये बधाई उन्होंने इसलिए भी दी क्योंकि देशभर में बसपा का जनधार काम होता जा रहा है. समर्थकों भी बिखरते जा रहे हैं. ऐसे में समर्थकों को एकजुट रखने का बीएसपी सुप्रीमो का यह प्रयास है. लगातार कम हो रहा पार्टी का रसूख : वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है. साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी खाता खोलने में भी सफल नहीं

हो पाई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन भी खराब हो रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन कर चुनाबी मैदान में उम्मीदवार उतारे. पार्टी को 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई. यूपी में चार बार सीएम रहें मायावती. यूपी में चार बार सीएम रहें मायावती. (विजय बमकपजय म्जट टीतंज) 2019 आम चुनाव के बाद खिसकने लगे वोटर : लोकसभा चुनाव 2019 के बाद पार्टी का कोर वोटर दलित बैंक भी खिसकने लगा. 2007 से 2012 तक 22 से 26 फीसदी वोट शेयर की पोलिटिक्स करने वाली बसपा सुप्रीमो अब यूपी में सिर्फ नौ से 10 फीसदी वोट शेयर पर अटकती दिख रही हैं. लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को फिर झटका लगा. पूरे देश में बसपा सिर्फ दो फीसदी वोट ही पा सकी. अब गृह कलह में फंसी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के रस्तातल में आने के पीछे एक बड़ा कारण मायावती की अपनी जिद भी है. पहले अपने समीप अशोक सिद्धार्थ को पार्टी

बायोटेक्नोलॉजी और एआई की क्रांति: नया अवसर, नई जिम्मेदारी

हैदराबाद: आज के दौर में बायोलॉजी एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहा है। सदियों तक वैज्ञानिक पौधों, जानवरों, सूक्ष्मजीवों और इंसानों को समझने के लिए मुख्य रूप से उन्हें देखते और उन पर प्रयोग करते आ रहे हैं। उसके बाद डीएनए (vch) की खोज हुई और बायोलॉजी की तस्वीर ही बदल गई, क्योंकि पता चला कि किसी भी जीवित प्राणी को बनाने और चलाने की सारी जानकारी उसके जेनेटिक मटीरियल में लिखी होती है। अब एक और नई क्रांति हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी के साथ मिलकर सिर्फ बायोलॉजी को पढ़ने तक नहीं रुक रही, बल्कि उसे समझने, उसके बारे में अनुमान लगाने और यहां तक कि जैविक सिस्टम डिजाइन करने की दिशा में आगे बढ़ने लगी है।

इस बदलाव का असर चिकित्सा, खेती, फार्मास्यूटिकल्स और पर्यावरण की सुरक्षा तक हो सकता है। भारत के लिए और खासतौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, यह एक असाधारण मौका है। हालांकि, इस मौके के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है। जीवन को डिजाइन करने की हमारी ताकत जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उस ताकत को उतनी ही सावधानी से संभालना भी जरूरी होता जाएगा। डीएनए पढ़ने और उसकी भाषा समझने तक

र जीवित कोशिका अपने निर्देश डीएनए में रखती है। ये निर्देश चार कनेकिल लेटर्स यानी A, T, C और G से लिखे जाते हैं। जीन (हमदर्मे) इसी विशाल बायोलॉजी चौंकर के तो हिस्से हैं, जिनमें प्रोटीन बनाने और कोशिका के अलग-अलग काम करने के निर्देश होते हैं, लेकिन जीन अकेले काम नहीं करते। डीएनए के दूसरे हिस्से किसी रिवच की तरह काम करते हैं और तय करते हैं कि कोई जीन कब, कहां और कितनी मजबूती से चालू या बंद होगा। इस लिहाज से डीएनए एक भाषा जैसा दिखाई देता है। जीन शब्दों की तरह होते हैं और रेगुलेटरी सीक्वेंस व्याकरण और विराम चिह्नों जैसी भूमिका निभाते हैं। कई सालों तक वैज्ञानिकों को ध्यान ज्यादातर उन्हीं जीन पर रहा, जो प्रोटीन को कोड करते हैं। जीनोम के जो बड़े हिस्से सीधे प्रोटीन नहीं बनाते थे, उन्हें कई बार यूं ही “जंक डीएनए” कह दिया जाता था। अब हम जानता हैं कि इस नॉन-कोडिंग डीएनए का बड़ा हिस्सा अहम रेगुलेटर की भूमिका निभाता है।

इस स्टडी के कई गहरे मायने हैं। कोई बीमारी सिर्फ इसलिये नहीं होती कि कोई जीन खराब है। कई बार एक बिल्कुल सामान्य जीन गलत समय पर चालू या बंद हो जाए, तो भी बीमारी हो सकती है। यही बात खेती से जुड़ी अहम खुरियों पर भी लागू होती है। सूखा सहने की क्षमता, बीमा, रियों से लड़ने की ताकत, खारापन झेलने की क्षमता और पैदावार, ये सब जीन और नियामक सीक्वेंस के कठिन नेटवर्क पर निर्भर करते हैं। हमान जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के तेज विकास ने जैविक जानकारी का विशाल भंडार खड़ा कर दिया है। अब चुनौती सिर्फ डेटा हासिल करने की नहीं रही। असली चुनौती उस डेटा से छिपे गतत्व को समझने की है और यही एआई बदलाव लाने वाली साबित हो रही है। जब एआई जैविक पैटर्न समझने लगती है आज के एआई सिस्टम बहुत बड़े यानी विशाल जैविक डेटासेट को खंगाल सकते हैं और ऐसे रिश्ते पकड़ सकते हैं, जिन्हें इंसानों के लिए पहचानना बेहद मुश्किल होता। वो डीएनए सीक्वेंस का विश्लेषण कर सकते हैं, प्रोटीन की संरचना का अनुमान लगा सकते हैं, बीमारियों से जुड़े म्यूटेशन पहचान सकते हैं और जीनों के आपसी संबंध सामने ला सकते हैं।

अल्फाफोल्ड की कामयाबी ने बायोलॉजी में एआई की संभावनाएं साफ कर दी हैं। इसने प्रोटीन की संरचना का अनुमान लगाने में एआई की असाधारण क्षमता दिखाई है। इससे साबित हुआ कि कंप्यूटर जैविक जानकारी को विशाल भंडाल से बायोलॉजी के जरूरी नियम सीख सकते हैं। अगला कदम इससे भी



ज्यादा रोमांचक है

जीनोम लैंग्वेज मॉडल (हमदवउम संधनंहम उवकमसे) कहे जाने वाले एआई सिस्टम डीएनए सीक्वेंस को कुछ हद तक इंसानी भाषा की तरह देखते हैं। जैसे कोई लैंग्वेज मॉडल शब्दों और वाक्यों के बीच में पैटर्न सीखता है, ठीक वैसे ही ये सिस्टम डीएनए सीक्वेंस के पैटर्न को सीखते हैं। पर्याप्त जीनोमिक जानकारी मिल जाए तो ये अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि कौन-से सीक्वेंस काम करने लायक होंगे और अपनी बढ़ती क्षमता के साथ नए सीक्वेंस भी तैयार करने लगे हैं। कंप्यूटर और बायोलॉजी के रिश्ते में यह एक बुनियादी बदलाव है। हम अब “देखो ६ समझो ६ बदलो” (देखतअम ६ न्दकमतैज्दक ६ डवकपति) के रास्ते से आगे बढ़कर “पढ़ो ६ अनुमान लगाओ ६ डिजाइन करो ६ परखो ६ सीखो” (लंक ६ च्मकपवज ६ क्मपहद ६ ज्मेज ६ स्मंतद) की तरफ जा रहे हैं। एआई से डिजाइन किए गए बैक्टीरियोफेज इस नई क्षमता के सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शनों में से एक। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट (ताब प्देजपजनजम) से जुड़े रिसर्चर्स के काम में दिखाई दिया है। उन्होंने दुनिया के बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (इंर) को निशाना बनाया। एंटीबायोटिक्स ने चिकित्सा की दुनिया बदल दी, लेकिन बैक्टीरिया लगातार उनके खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं। जो संक्रमण एक दौर में आसानी से ठीक हो जाते थे, उन्हें अब काबू में रखना काफी मुश्किल होता जा रहा है।

प्रकृति ने हमें एक औरहथियार दिया है, जिसमें बैक्टीरियोफेज (इंक्जम, तापवबीहम) कहते हैं। इसे स्क्वैप में फेज” (वीहमे) कहा जाता है। ये ऐसे वायरस हैं, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। इंसानों को संक्रमित करने वाले वायरस से अलग, बैक्टीरियोफेज किसी खास बैक्टीरिया के प्रति बेहद विशिष्ट हो सकते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक फेज को एंटीबायोटिक्स के विकल्प या उनके पूरक के तौर पर परख रहे हैं। हाल ही में आई ये सफलता इस विचार को बिल्कुल नए इलाके में लेकर चली गई है। रिसर्चर्स ने एवो 1 और एवो 2 (एव 1 और एव 2) नाम के एआई मॉडल इस्तेमाल किए, जो जीनोम सीक्वेंस के बहुत बड़े कलेक्शन से पैटर्न सीखते हैं। प्रकृति में पहले से मौजूद किसी बैक्टीरियोफेज को खोजने के बजाय, रिसर्चर्स ने एआई से बिल्कुल नए बैक्टीरियोफेज जीनोम डिजाइन करने को कहा। एआई के बनाए सैकड़ों डिजाइन्स को प्रयोगशाला में तैयार करके टेस्ट किया गया, गौर करने वाली बात यह रही कि इनमें से 16 जीनोम ने ऐसे काम करने वाले बैक्टीरियोफेज पैदा किए, जो एस्केरिकिया कोलाई (भीमंतपवीप ववसप), यानी ई-कोलाई, नाम के बैक्टीरिया को संक्रमित करके मार सकते थे। कुछ में उस प्राकृतिक वायरस से अलग जैविक गुण दिखाई दिए, जिसे शुरुआती आधार बनाया गया था, इसके अलावा नए फेज के मेल ने प्रयोगशाला के प्रयोगों में बैक्टीरिया के प्रतिरोध को भी पार कर लिया। यह एक असाधारण वैचारिक उपलब्धि है।

पहली हार एआई ने जैविक सीक्वेंस का विश्लेषण करने से आगे बढ़कर एक पूरा काम करने वाला वायरल जीनोम लिखने में मदद करने की क्षमता दिखाई है। इससे तैयार हुआ वायरस सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं

है, वो प्रयोगशाला में बनाकर परखने पर काम करता है। यहां इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के खिलाफ थे यानी ये इंसानों को संक्रमित करने के लिए डिजाइन किए गए वायरस नहीं थे, रिसर्चर्स ने अपनी सुरक्षा रणनीति के हिस्से के तौर पर जानबूझकर काम को सिर्फ बैक्टीरिया वाले टारगेट तक सीमित रखा। हालांकि, फिर भी इस उपलब्धि की अहमियत फेज थेरेपी से कहीं आगे तक जाती है। “जीवन को डिजाइन करने” का नया आयाम आप कल्पना कीजिए कि भविष्य में कोई वैज्ञानिक एआई सिस्टम को अपनी जैविक समस्या बताता है। वो कहता है, “मुझे ऐसी फसल चाहिए जो बैक्टीरिया का प्रतिरोध कर सके और सूखा व ज्यादा तापमान भी सह सके।” या वह कहता है, “मुझे ऐसा मॉलीब्डम चाहिए, जो कैसर से जुड़े इस प्रोटीन को चुनकर निशाना बना सके।” या फिर, “मुझे ऐसा जैविक सेंसर चाहिए जो इस प्रदूषक का पता लगा सके।” उसके बाद एआई विशाल जैविक डेटासेट खंगाल सकता है, काम के पैटर्न पहचान सकता है, संभावित समाधान तैयार कर सकता है और प्रयोग के लिए उम्मीदवारों को सुझा भी दे सकता है। उसके बाद प्रयोगशाला उन अनुमानों को भी परखेगी। प्रयोग के नतीजे वापस एआई सिस्टम के पास जाएंगे, जिससे उसके अगले अनुमान और बेहतर होंगे। इससे एक काफी पावरफुल साइकिल बनती है।

एआई डिजाइन ६ प्रयोगशाला में प्रयोग ६ जैविक डेटा ६ एआई की सीख ६ बेहतर डिजाइन

इस कारण बायोटेक्नोलॉजी धीरे-धीरे इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच जैसी होती जा सकती है, जहां जैविक सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और बेहतर बनाया जाता है। भारत के लिए बड़े अवसर इस बदलाव की भारत के लिए काफी खास अहमियत है। हैदराबाद में जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन, बायोटेक्नोलॉजी और इफोमैशन टेक्नोलॉजी का पहले से ही एक असाधारण इकोसिस्टम मौजूद है। सीसीएमपी (व्बट), सीडीएफडी (व्बट), यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, एआईजी हॉस्पिटल्स (एफ व्बेचपजर्स) और इक्वीसैट (व्बे-ए) जैसे संस्थान, जीनोम वैली और यहां की बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा इंडस्ट्री मिलकर इसे मजबूत बुनियाद देते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना खेती की गंभीर समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। गर्मी का तनाव, सूखा, पानी की कमी, खारापन, नए कीट और बीमारियां भी हो रही हैं। एआई से लैस जीनोमिक्स जलवायु के प्रति मजबूती (वसपउजम तामेपसपमदवम) से जुड़े जेनेटिक नेटवर्क पहचानने और फसलों की बेहतर किस्में और तरीकों को जल्द से जल्द डेवलप करने में मदद कर सकती है। एआई प्रिसिजन एग्रीकल्चर में भी मदद कर सकती है। सैटेलाइट पिक्चर्स, ड्रोन से ली गई फोटो, मिट्टी की जानकारी, मौसम के पैटर्न और फसल के डेटा का विश्लेषण करके आगे चलकर किसानों को सिंचाई, पोषक तत्वों के मैनेजमेंट और बीमा रियों की रोकथाम पर उनके इलाके के हिसाब से सलाह दी जा सकेगी। चिकित्सा में एआई से लैस जीनोमिक्स बीमारी की पहचान, नई दवाओं की खोज और व्यक्ति के हिसाब से इलाज को तेज कर सकती है। औद्योगिक बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम, वैक्सीन, बायोमोलिक्जूल और सूक्ष्मजीवों से जुड़ी प्रक्रियाएं डिजाइन करने में मदद मिल सकती है।

अरावली संकट: 30 नवंबर को तय होगा भविष्य, वैज्ञानिक सोच और जन-भागीदारी क्यों है जरूरी?

उस पुराने आदेश में सरकार द्वारा दी गई अरावली की एक परिभाषा को स्वीकार किया गया था, जिसके तहत केवल उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना गया था जो आस-पास की जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हों, और जिनके बीच की दूरी 500 मीटर के भीतर हो।

विवाद क्या है?

पर्यावरण समूहों और जानकारों ने इस परिभाषा की कड़ी आलोचना की है, भारतीय वन सर्वेक्षण (थु) के आंकड़ों से पता चला है कि अगर 100 मीटर की यह शर्त लागू की गई, तो बहुत सी छोटी पहाड़ियां इस परिभाषा से बाहर हो जाएंगी। एक आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार, राजस्थान में 20 मीटर या उससे ऊंची 12,081 अरावली पहाड़ियों में से केवल 1,048 पहाड़ियां (यानी सिर्फ 8.7%) ही इस 100 मीटर की शर्त को पूरा करती हैं। वहीं, अगर अरावली की सभी 1,18,575 पहाड़ियों को देखा जाए, तो 90% से अधिक पहाड़ियां इस परिभाषा में फिट नहीं बैठती हैं।

इस वजह से राजस्थान और हरियाणा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों को डर है कि इस परिभाषा के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान होगा और अवैध खनन बढ़ेगा। आलोचकों का कहना है कि इस परिभाषा से अरावली के एक बहुत बड़े हिस्से में चूना पत्थर (लाइमस्टोन) के खनन और पत्थर तोड़ने वाले कशरों का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वतमाला का इवाई दृश्य (फाइल) (छप्रेसुप्रीम कोर्ट का इस्तकैप29 दिसंबर 2025 को, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक वेंकेशन बेंच ने 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरणविदों के बीच 100-मीटर के नियम के “गलत अर्थ निकालने और इसके गलत इस्तेमाल” की आशंकाओं को लेकर “गहरी चिंता” है। कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान (नव उजजन) लिया और इस परिभाषा से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की दोबारा जांच करने के लिए एक हाई-पावर्ड, स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने विशेष रूप से कई “गंभीर कमियों” की तरफ इशारा किया।

क्या पहाड़ियों के बीच 500 मीटर की दूरी तय करने से संरक्षित क्षेत्र बहुत कम हो जाएगा?

क्या इस परिभाषा से अरावली के कई क्षेत्र “गैर-अरावली” बन जाएंगे, जिससे वहां खनन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा? क्या यह दावा वैज्ञानिक रूप से सही है कि केवल 1,048 पहाड़ियां ही अरावली की परिभाषा में आती हैं? जब तक यह नई जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक पूरे अरावली क्षेत्र में कोई नया खनन पट्टा (माइनिंग लीज) या उसका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नए खनन पट्टों पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं, और यह प्रतिबंध पूरी अरावली शृंखला पर समान रूप से लागू होता है।

हाई-पावर्ड समिति के बारे में जाने इस स्वतंत्र समीक्षा को करने के लिए भारतीय पान्की अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (व्ब्स) की महानिदेशक कंचन देवी की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसके सदस्यों में शामिल हैं: डॉ. सुभाष आशुतोष, भारतीय वन सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार शर्मा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक बृज मोहन सिंह राठी, पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव प्रो. अशोक के. भटनागर, दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख

बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स के प्रोफेसर जगद, 1श कृष्णस्वामी और केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के प्रो. लक्ष्मीकांत शर्मा को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। समिति को निर्देश दिया गया है कि वह केवल ऊंचाई की एक शर्त पर निर्भर रहने के बजाय भूवैज्ञानिक, जलवैज्ञानिक और पारिस्थितिक



कारकों को शामिल करते हुए नए नियम तय करें। समिति की मुख्य जिम्मेदारियों में क्या जांचना शामिल है क्या 100 मीटर की ऊंचाई वाली शर्त वैज्ञानिक रूप से सही है? क्या अरावली की पहाड़ियां 500 मीटर से अधिक की दूरी पर होने के बावजूद भी आपस में जुड़ी हुई एक प्राकृतिक प्रणाली बनाती है?

क्या दो पहाड़ियों के बीच खाती बची जगहों में खनन की अनुमति दी जानी चाहिए? समिति के कार्यों की समय-सीमा और हालिया घटनाक्रमसुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में समिति को 31 अगस्त 2026 तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। जब समिति ने 28 फरवरी 2027 तक छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा, तो कोर्ट ने 7 सितंबर 2026 को इस अनुरोध को खारिज कर दिया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की “ऐसा लग रहा है, जैसे समिति मेरे रिटायरमेंट तक मामले को टालना चाह रही है। पीठ ने समिति को 30 नवंबर 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का कड़ा निर्देश दिया और चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर समिति का पुनर्गठन कर दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “समिति अरावली मामले पर रिपोर्ट सौंपने के लिए दिन-रात काम करे।” कोर्ट ने समिति को राजस्थान और गुजरात के आदिवासी समुदायों सहित सभी पक्षों के साथ व्यापक बातचीत करने का भी निर्देश दिया। जरूरत पड़ने पर विशेष मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट देने की अनुमति दी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वतमाला का इवाई दृश्य (फाइल) (छप्रे अरावली का क्या महत्व है अरावली पर्वत शृंखला थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने के लिए एक बेहद जरूरी प्राकृतिक दीवार का काम करती है। यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में खेती और पीने के पानी की आपूर्ति करने वाले भूजल स्रोतों को रिचार्ज करती है। यहां अनोखे जीव-जंतु व वनस्पतियां पाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्वत शृंखला को उत्तर-पश्चिमी भारत की “अनिवार्य पारिस्थितिक और सामा. जिक-आर्थिक रीढ़” माना है।

इस विशेषज्ञ समीक्षा का नतीजा यह तय करेगा कि क्या अरावली को एक लगातार जुड़े हुए प्राकृतिक तंत्र के रूप में सुरक्षा मिलेगी, या फिर इसके बड़े हिस्से खनन और निर्माण कार्यों के लिए असुरक्षित छोड़ दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही आदेश को रोकना और नए वैज्ञानिक मूल्यांकन की मांग करना, इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है और भारत के सबसे पुराने व प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के लिए दाव कितना ऊंचा है, यह भी साफ करता है।

ऊंचाई के आधार पर तय की गई 100 मीटर की प्रस्तावित सीमा, नाजुक ढलानों और बफर जोन को विनाशक, 1री कर्मशियल माइनिंग और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के खतरे में डाल सकती है। ग्रामीण समुदायों और पर्यावरण विशेषज्ञों की भी यही चिंता है। उनका लंबे समय से कहना है कि इतनी सीमित परिभाषा के कारण इस पर्वत शृंखला का एक बड़ा हिस्सा चूना पत्थर की माइनिंग और पत्थर तोड़ने के काम (स्टोन क्रशिंग) की चपेट में आ सकता है।

इसके नतीजे पहले ही दिख रहे हैं: स्थानीय ग्रामीणों में सांस की गंभीर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं, भूजल का स्तर गिरना, जैव विविधता का नुकसान और एक प्राचीन प्राकृतिक

इलाके को कभी न ठीक होने वाला नुकसान। सिर्फ ऊंचाई पर आधारित परिभाषा अरावली की पारिस्थितिक, जल-संबंधी और भूवैज्ञानिक निरंतरता को नहीं समझ पाती है। इससे एक जीवित पर्वत प्रणाली के अलग-अलग छोटी पहाड़ियों में बंटने का खतरा है, जिन्हें एक-एक करके खत्म किया जा सकता है।

सिर्फ ऊंचाई पर आधारित परिभाषा अरावली की पारिस्थितिक, जल-संबंधी और भूवैज्ञानिक निरंतरता को नहीं समझ पाती है। इससे एक जीवित पर्वत प्रणाली के अलग-अलग छोटी पहाड़ियों में बंटने का खतरा है, जिन्हें एक-एक करके खत्म किया जा सकता है।

अरावली पर्वत शृंखला की बेहतर परिभाषा के लिए भूवैज्ञानिक मानदंडों में चट्टानों की निरंतरता, संरचनात्मक विशेषताएं (जैसे फॉल्ट लाइन और फोल्ड बेल्ट), भूजल रिचार्ज जोन और खास खनिजों की मौजूदगी जैसे कारकों को शामिल किया जाना चाहिए। ये कारक ऊंचाई की तुलना में सीमा तय करने का कहीं अधिक ठोस आधार प्रदान करते हैं।

जैसा कि आप जानते होंगे, स्वतंत्र वैज्ञानिकों (जिनमें मैं भी शामिल हूँ) ने पहले बने फैसले के गठन के खिलाफ याचिका दायर की थी, क्योंकि उसमें पारिस्थितिक और जल-संबंधी मामलों के विविध विशेषज्ञों की कमी थी। हाल की अखबारों की खबरों से पता चलता है कि ग्राफीन टेक्निकल कमेटी के साथ अपनी सीमित बातचीत से नाखुश हैं, जिस कमेटी का काम पूरी पर्वत शृंखला का भविष्य तय करना हो, वह लोगों से दूर, अपारदर्शी या बिना सही प्रतिनिधित्व वाली नहीं दिखनी चाहिए। असरदार होने के लिए, इस कमेटी को जनता का भरोसा जीतने और इन शिकायतों को दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए।

कमेटी को जमीनी स्तर पर निवासियों के साथ सीधे जुड़ना चाहिए—जैसे कि व्यवस्थित बातचीत, सभी को शामिल करने वाली जन-सुनवाई और व्यापक फील्ड विजिट के जरिए। ठोस फील्डवैक और जरूरी डेटा इकट्ठा करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी परिभाषा, जिसमें उस पर्वत शृंखला पर निर्भर लोगों के वास्तविक अनुभवों को शामिल न किया गया हो, वैज्ञानिक रूप से अधूरी और सामा. जिक रूप से अन्यायपूर्ण होगी।

“नवतमउम ब्नतज हंतअंससप”पससे लुअरावली पर्वत शृंखला को संरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि मुख्य वैज्ञानिक सवालों के जवाब मिल सकें। अरावली की ऐसी

एशियन गेम्स में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय और एक पाकिस्तानी शामिल



एशियन गेम्स का 20वां एडिशन इन दिनों जापान में जारी है। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत और श्रीलंका की टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। रविवार को श्रीलंका ने पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 8 विकेट से मात दी। जबकि भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और 20 ओवर में 195/4 रन बनाए, उसके बाद बांग्लादेश को 81 रनों पर ऑलआउट कर दिया। केवल तीन बल्लेबाजी ही दहाई का आंकड़ा छू पाईं। नंदनी शर्मा और दीप्ति शर्मा ने तीन-तीन विकेट

लिए, जबकि श्री चरानी ने दो विकेट लिए। एशियन गेम्स एशियन गेम्स (जम्) इस मैच में दाएं हाथ की बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 49 गेंदों में नाबाद 100 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 204.08 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिसमें 3 चौकों और 9 छक्के शामिल थे। इसके साथ वो एशियाई खेलों में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं। शेफाली वर्मा की ऐतिहासिक सेंचुरी शेफाली ने अपनी शतकीय पारी के दौरान कई रिकॉर्ड बनाए। एशियन गेम्स शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने के साथ साथ वह 2020 में शतक लगाने वाली तीसरी भारतीय महिला भी बनीं।

इसके अलावा वो 2023 में यशस्वी जायसवाल के शतक के बाद एशियाई खेलों में ऐसा कारनामा करने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज हैं। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची (जम्) एशियन गेम्स में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज एशियन गेम्स में अब तक केवल पांच बल्लेबाज ही शतकीय पारी खेल सके हैं, जिसमें बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 49 गेंदों में नाबाद 100 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 204.08 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 9 छक्के शामिल थे। इसके साथ वो एशियाई खेलों में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गईं। शेफाली वर्मा की ऐतिहासिक सेंचुरी शेफाली ने अपनी शतकीय पारी के दौरान कई रिकॉर्ड बनाए। एशियन गेम्स शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने के साथ साथ वह 2020 में शतक लगाने वाली तीसरी भारतीय महिला भी बनीं।

आम जनता को बड़ा झटका! अक्टूबर और दिसंबर में फिर बढ़ सकती है आपके लोन की म्डप रिपोर्ट



देश में होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की मासिक किस्त (म्डप) चुकाने वाले करोड़ों लोगों के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की शोध इकाई यानी एसबीआई रिसर्च ने अपनी ताजा रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, खुदरा महंगाई दर में होने वाली संभावित बढ़ोतरी और चीतरफा बढ़ते दबाव को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (रुप) आगामी अक्टूबर और दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में ब्याज दरों में 25-25 बेसिस पॉइंट (कुल 0.50%) का इजाफा कर सकता है। क्या बढ़ेगी ब्याज दरें और क्या है वजह?

पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण काम कर रहे हैं। खुदरा महंगाई दर का 6.5% के पार जाना: देश में खुदरा महंगाई दर अगस्त में बढ़कर 4.82 फीसदी पर पहुंच गई है, जो जुलाई में 4.45 फीसदी थी। ग्रामीण इलाकों में यह दर और भी अधिक 5.23 फीसदी रही है। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि आने वाले महीनों में यह महंगाई दर 6.5 फीसदी के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर जाएगी। यह सितंबर में 5.88 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 6.70 फीसदी तक पहुंच सकती है, जिसके बाद वर्ष 2027 की शुरुआत में ही यह 8 फीसदी से नीचे आ जाएगी।

कच्चे तेल की कीमतों और आयातित महंगाई: पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। भारतीय कूल बारकेट की कीमत जुलाई के 82.04 डॉलर से बढ़कर सितंबर में 109.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है। इसके चलते आयातित महंगाई पहले ही 7.75 फीसदी की ऊंची दर पर चल रही है, जो घरेलू बाजार में चीजों की कीमतों बढ़ा रही है। महंगाई का सामान्यीकरण और बढ़ता दबाव रिपोर्ट में सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर जताई गई है कि महंगाई अब केवल पुर्नित वस्तुओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका सामान्यीकरण (जमदमतसपेजपवद) शुरू हो चुका है। एसबीआई रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2026 में खुदरा महंगाई सूचकांक में योगदान देने वाली वस्तुओं की संख्या जो

ज20 में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, बाबर-बटलर भी छूटे पीछे

ज20 में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, बाबर-बटलर भी छूटे पीछे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने ज20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वो अब ज20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। यही नहीं बल्कि वो महिलाओं के अलावा पुरुष क्रिकेटर्स को भी इस मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है। मंधाना ने ये बड़ी उपलब्धि रविवार को एशियाई खेलों में बांग्लादेश महिला टीम के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मैच में 19 गेंदों पर 37 रनों की शानदार पारी खेलकर हासिल की। जिसमें उन्होंने पांच चौके और दो छक्के भी लगाए। 30 वर्षीय बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति को ये रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए मैच से पहले सात रन की जरूरत थी। उन्होंने तीसरे ओवर में बांग्लादेश की तेज गेंदबाज मारुफा अख्तर की आखिरी दो गेंद पर लगातार चौके जड़कर यह उपलब्धि हासिल की। स्मृति मंधाना स्मृति मंधाना (रुप) इसके साथ स्मृति मंधाना ने महिला ज20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली सूची में न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेटर सुजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 4758 टी20 इंटरनेशनल रन हैं। अब मंधाना को 171 पारियों में 4788 टी20 इंटरनेशनल रन हो गए हैं। जबकि भारत की कप्तान हरमनप्रीत



कौर 4,287 रन के साथ तीसरे और श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टु 4,282 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं। महिला ज20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज 1 - स्मृति मंधाना (भारत): 4,788 रन 2 - सुजी बेट्स (न्यूजीलैंड): 4,758 रन 3 - हरमनप्रीत कौर (भारत): 4,284 - चमारी अटापट्टु (श्रीलंका): 4,282 रन मंधाना ने बाबर-बटलर को भी छोड़ा पीछे। इस लिस्ट में स्मृति मंधाना केवल महिला खिलाड़ियों से ही आगे नहीं निकली हैं, बल्कि वो मंस क्रिकेटरों से भी काफी ज्यादा आगे निकल गई हैं। वो पुरुष ज20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

— बाबर आजम और जॉस बटलर से अब और ज्यादा आगे निकल गई हैं। ज20 में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास ज20 में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास (रुप) ज20 में सबसे ज्यादा रन (पुरुष और महिला) 1 - स्मृति मंधाना (भारत): 4,788 रन 2 - सुजी बेट्स (न्यूजीलैंड): 4,758 रन 3 - बाबर आजम (पाकिस्तान): 4,596 रन 4 - जॉ बटलर (इंग्लैंड): 4,292 रन 5 - हरमनप्रीत कौर (भारत): 4,287 रन 6 - रोहित शर्मा (भारत): 4,231 रन बता दें कि महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड की जैन ब्रिट्टिन के नाम है। उनके नाम महिला टेस्ट क्रिकेट में 1935 रन हैं। जबकि महिला वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज हैं, जिनके नाम वनडे में 7805 रन हैं। वहीं महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मंधाना के नाम हो गया है।

वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स, जानें भारत में कब और कहाँ देख सकेंगे मैच?

ऑस्ट्रेलिया की टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर है। जहां उसे तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। ये सीरीज 2027 वर्ल्ड कप के लिहाज काफी अहम समझी जा रही है, क्योंकि जिम्बाब्वे टूर्नामेंट का सह मेजबान है। सीरीज का पहला मैच आज, 15 सितंबर को हारे के हारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम जिम्बाब्वे ने हाल ही में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ ज20 ट्राई सीरीज खेलकर इस सीरीज में कदम रख रही है, जिसमें उन्होंने फाइनल मुकामले में साउथ



अफ्रीका से 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी धरती पर

बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलकर आ रहा है, जो 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई थी। जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की टीम जिम्बाब्वे के सामने काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन इस मजबूत किले को भेदना नामुमकिन भी नहीं है। इसलिए जिम्बाब्वे अब तक खेले गए 33 वनडे मैच में तीन बार ऑस्ट्रेलिया को मात दे चुकी है। जबकि 1 मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम मिशेल मार्श,

पंजाब: त्योहारों से पहले सरकारी कर्मचारियों को बंपर तोहफा, व। में सीधे 8: की भारी बढ़ोतरी



इ: पंजाब की भगवत मान सरकार ने राज्य के करीब आठ लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को त्योहारों से ठीक पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते (व।) में 8 फीसदी की बढ़ोतरी करने का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवत मान और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस फैसले पर मुहर लगी, जिससे पिछले कई हफ्तों से चला आ रहा गतिरोध और राज्यव्यापी आंदोलन अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। दो किस्तों में मिलेगा लाभ, अक्टूबर से बढ़ेगी सैलरी बैंकेट से मिली जानक। 1री के मुताबिक, इस 8: की बढ़ोतरी के बाद राज्य के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता अब 42: से बढ़कर 50: हो गया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि इस बड़े हुए भत्ते को 4-4 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी किया जाएगा, यह नई दरें सितंबर 2026 के वेतन से ही प्रभावी मान ली गई हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि 1 अक्टूबर 2026 को कर्मचारियों के खातों में जो सैलरी आएगी, वह भारी बढ़ोतरी के साथ क्रेडिट होगी। सरकारी खजाने पर 2250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ इस बड़े वित्तीय फैसले से जहां राज्य के लाखों परिवारों को त्योहारों के सीजन में बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी,

वहीं पंजाब के सरकारी खजाने पर हर महीने करीब 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा, हालांकि, सरकार का कहना है कि वे इस खर्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कर्मचारियों की गरिमा उनकी सर्वाच्च प्राथमिकता है। वाद से सुलझा विवाद: महिला कर्मचारियों को भी बड़ी राहत लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारी यूनियनों के साथ मुख्यमंत्री भगवत मान ने खुद बातचीत की कमान संभाली। उन्होंने टकराव का रास्ता छोड़कर संवाद का जरिया चुना। इस बैठक में न सिर्फ डीए बढ़ाने पर सहमति बनी, बल्कि मुख्यमंत्री ने भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हर महीने अनिवार्य रूप से बैठक करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही, सरकार ने महिला कर्मचारियों की सहायित को ध्यान में रखते हुए एक और संवेदनशील फैसला लिया है। अब राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को उनके घर से 40 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही पोस्टिंग दी जाएगी, ताकि वे अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को बिना किसी तनाव के निभा सकें। 70,000 युवाओं को पारदर्शी नौकरियां शीब 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों की तलाश के निमा सकें। 70,000 युवाओं को पारदर्शी नौकरियां मुख्यमंत्री मान ने इस मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए निक व्यवस्था की रीढ़ हैं, एक संतुष्ट। मुहैया कराई हैं। इसके अलावा, पुरानी पेंशन योजना (वै) और अन्य लंबित भत्तों पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

कर्मचारी ही सिस्टम को बेहतर बना सकता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक बिना किसी भ्रष्टाचार और पूरी पारदर्शिता के साथ ककराव का रास्ता छोड़कर संवाद का जरिया चुना। इस बैठक में न सिर्फ डीए बढ़ाने पर सहमति बनी, बल्कि मुख्यमंत्री ने भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हर महीने अनिवार्य रूप से बैठक करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही, सरकार ने महिला कर्मचारियों की सहायित को ध्यान में रखते हुए एक और संवेदनशील फैसला लिया है। अब राज्य की सभी महिला कर्मचारियों को उनके घर से 40 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही पोस्टिंग दी जाएगी, ताकि वे अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को बिना किसी तनाव के निभा सकें। 70,000 युवाओं को पारदर्शी नौकरियां शीब 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों की तलाश के निमा सकें। 70,000 युवाओं को पारदर्शी नौकरियां मुख्यमंत्री मान ने इस मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए निक व्यवस्था की रीढ़ हैं, एक संतुष्ट। मुहैया कराई हैं। इसके अलावा, पुरानी पेंशन योजना (वै) और अन्य लंबित भत्तों पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

